

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8> छत्तीसगढ़ को महिला फुटबॉल ...



नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर एक्शन में केंद्र

संशोधन विधेयकों को पारित करने बुलाएंगे विशेष सत्र

विशेष सत्र 16 से 18 अप्रैल तक फिर बुलाया जाएगा

नई दिल्ली । संसद का विशेष सत्र 16 से 18 अप्रैल तक फिर बुलाया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू करने और संबंधित संशोधन विधेयकों को पारित करना है। मोदी सरकार ने बजट सत्र के समापन के बीच संसद की बैठकों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित न करने का बड़ा फैसला किया है। इसके बजाय, मोदी सरकार ने तय किया है कि सत्र के अंत में घोषणा की जाएगी कि संसद अगले निश्चित तिथि पर फिर से बैठक करेगी। इस विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण से जुड़े संवैधानिक और विधायी कदम उठाए जाएंगे।

संसद का बजट सत्र इस वर्ष 28 जनवरी को शुरू हुआ था और प्रारंभ में 2 अप्रैल 2026 तक पूरा करने का कार्यक्रम था। हालांकि, मोदी सरकार



अब बजट सत्र को कुछ दिनों के लिए बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसके पीछे मुख्य कारण नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन करना और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें सुनिश्चित करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बारे में एनडीए के घटक दलों और विपक्ष के कुछ क्षेत्रीय दलों के नेताओं के साथ अलग-अलग बैठकें कर आम सहमति बनाने की पहल की है। विशेष सत्र में पेश होने वाले संविधान संशोधन विधेयक के तहत नारी शक्ति वंदन अधिनियम में

संशोधन होगा। यह संशोधन महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। 2023 में पारित हुए विधेयक के लागू होने के लिए परिसीमन प्रक्रिया जरूरी थी। वर्तमान रूपरेखा के अनुसार, लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 की जाएगी, जिसमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इससे संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी और निर्णय प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी।

मोदी सरकार का उद्देश्य है कि संसद को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित न किया जाए, बल्कि इसे निश्चित तिथि पर फिर से बैठक के लिए बुलाया जाए। सूत्रों के अनुसार, अप्रैल की तीसरे सप्ताह में दो-तीन दिनों के लिए लोकसभा और राज्यसभा की

बैठक आयोजित की जा सकती है। इस सत्र के दौरान महिला आरक्षण और संसद में सीटों की वृद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, जिससे महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में मजबूती मिलेगी। विशेष सत्र का आयोजन महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे न केवल संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी, बल्कि नीति निर्धारण और विधायी प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी। सरकार का हिस्सेदारी बढ़ेगी और निर्णय प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी। सरकार का हिस्सेदारी बढ़ेगी और निर्णय प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी। सरकार का हिस्सेदारी बढ़ेगी और निर्णय प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी।



रायपुर। छत्तीसगढ़ की महिला फुटबॉल टीम ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स-2026 के पहले संस्करण में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में झारखंड को 1-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। टीम की कप्तान किरण पिस्टा की व्यक्तिगत प्रतिभा इस जीत की सबसे बड़ी वजह रही। मेज़बान राज्य ने जगदलपुर में ट्रेक एंड फील्ड प्रतियोगिताओं के अंतिम चरण में पुरुषों की 4x400 मीटर रिले में रजत और पुरुषों की 1500 मीटर में कांस्य पदक भी अपने नाम किया। वहीं झारखंड के शिव कुमार सोरेन ने 100 मीटर के बाद 200 मीटर में भी स्वर्ण जीतकर शानदार डबल पूरा किया। छत्तीसगढ़ की महिला टीम ने आक्रामक झारखंड के खिलाफ मिले एकमात्र मौके का पूरा फायदा उठाया, जब कप्तान किरण पिस्टा ने 61वें मिनट में विपक्षी डिफेंस की गलती का फायदा उठाते हुए गोल दागा। इसके बाद मेज़बान टीम ने बढ़त को अंत तक बरकरार रखते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। किरण ने कहा, यह हमारे लिए बहुत खास पल है क्योंकि पहली बार इतने सारे दर्शक हमें समर्थन देने आए। मुझे बहुत खुशी है कि हम अपने घरेलू दर्शकों के सामने स्वर्ण पदक जीत सके।

गैस की कीमतें बढ़ रहीं और आप चर्चा नहीं चाहते: खड़गे

नई दिल्ली । राज्यसभा में बुधवार को एलपीजी और गैस की किल्लत के मुद्दे पर सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों की तीखी तकरार देखने को मिली। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर शॉर्ट ड्यूरेशन चर्चा की डिमांड की और कहा कि हम जो सुझाव देते हैं, वह सहमत नहीं होते। विपक्ष के नेता ने सरकार को घेरते हुए कहा कि ये जब चाहे, बिल लाते हैं. जब चाहे, चर्चा के लिए तैयार होते हैं. जब चाहे, तब स्टेटमेंट देते हैं. संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार की बात विपक्षी दल ही नहीं सुनते. दरअसल, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैंने एक बार नहीं, दो बार

नियम 176 के तहत संक्षिप्त चर्चा के लिए लेटर दिया. उसके लिए उनके पास समय नहीं है. उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया तबाह हो रही है, एलपीजी और गैस के लिए, इधर दाम बढ़ रहे हैं. खड़गे ने कहा कि कीमतें बढ़ रही हैं और आप चर्चा नहीं चाहते. हम जो सुझाव देते हैं, वह सहमत नहीं होते. खड़गे ने कहा कि वे (सत्तापक्ष) जो चाहते हैं, उसे जबरदस्ती रखते हैं और ध्वनिमत करा लेते हैं।

दमनकारी ताकतों से निपटने मजबूत होना होगा: ओवैसी

गुवाहाटी। अमस के मुख्यमंत्री हिमांत बिस्वा सरमा की कथित नमरामांी पर निशाना साधकर ओवैसी ने कहा कि हालात बेहद खराब हैं। इस स्थिति में दमनकारी ताकतों से निपटने के लिए एआईएमआईएम के माध्यम से मुस्लिम समुदाय के नेतृत्व को मजबूत करना होगा। लोकतंत्र में सिर्फ नारे लगाने से काम नहीं चलता। हमें मतदान के माध्यम से सुनिश्चित करना होगा कि सरमा को उनकी प्रतिगामी राजनीति का स्पष्ट संदेश मिले।ओवैसी ने कहा कि इसके लिए हमें एकजुट रहना होगा।

चुनाव के दिन मतदान करके आपको जवाब देना होगा। लोकतंत्र में आपका वोट एक शक्तिशाली हथियार है। उन्होंने आगामी चुनावों में भाजपा की कथित बढ़त के दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इस पर विश्वास नहीं करते। हमारा प्रयास राज्य की राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत करना है। ओवैसी आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अखिल भारतीय संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (एआईयूडीएफ) के प्रचार अभियान से पहले बुधवार को असम पहुंचे।

स्टील प्लांट से ब्रिज तक सब तबाह... ईरान पर डबल अटैक

नई दिल्ली । अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ अपने हमलों को और तेज कर दिया है। इन हमलों में तेहरान के एक सदी पुराने मेडिकल रिसर्च सेंटर, राजधानी के पास एक पुल और दो बड़े स्टील प्लांट्स को निशाना बनाया है।ईरान की ओर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है, जबकि दोनों देश अपने हमलों को जारी रखे हुए हैं।राजधानी तेहरान को पश्चिमी शहर करज से जोड़ने वाले हाईवे ब्रिज पर भी हमला किया गया। अल्बोर्ज प्रांत के डिप्टी गवर्नर ने ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी दुस्ख को बताया कि इस हमले में दो लोगों की मौत हो गई।अमेरिका और इजरायल के हमलों से ईरान की दो सबसे बड़ी स्टील कंपनियां भी प्रभावित हुई हैं। अहवाज में खुजिस्तान स्टील कंपनी और इस्फाहन प्रांत में मोबारकेह स्टील कंपनी को पूरी तरह से बंद करना पड़ा है। इन हमलों से ईरान की औद्योगिक क्षमता पर गंभीर असर पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनेल्ड ट्रंप ने बुधवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि अमेरिका ईरान में अपने मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने के बहुत करीब पहुंच गया है। हालांकि, उन्होंने संघर्ष के समाप्त होने की कोई निश्चित समयसीमा नहीं बताई। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपने लक्ष्यों की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है।

न्यायिक अधिकारियों के घेराव मामले की जांच एनआईए को सौंपी

कोलकाता। भारतीय निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में सात न्यायिक अधिकारियों के घेराव की घटना की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दी है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में राज्य प्रशासन की कड़ी आलोचना करते हुए पश्चिम बंगाल को सबसे अधिक ध्ववीकृत राज्य बताया था। यह टिप्पणी उस घटना के बाद आई, जिसमें मतदाता सूची के एसआईआर के दौरान इयूटी पर तैनात सात न्यायिक अधिकारियों को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया और बंधक बना लिया था। कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई या एनआईए से कराने का निर्देश दिया था।चुनाव आयोग ने 2 अप्रैल को एनआईए को भेजे पत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बुधवार को हुई इस घटना की जांच करने को कहा। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, एनआईए की टीम शुक्रवार को पश्चिम बंगाल पहुंचेगी। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में मतदाता सूची से नाम कोट जाने के विरोध में सात न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने के आरोप में पुलिस ने बृहस्पतिवार को 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में इंडियन सेक्युलर फ्रंट के उम्मीदवार मौलाना शाहजहां अली भी शामिल हैं।

एलपीजी की कोई कमी नहीं, सिर्फ माहौल बना रहे: कमलनाथ

नईदिल्ली। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमल नाथ ने गुस्वार को गैस और एलपीजी की कमी की खबरों को खारिज करते हुए इन्हें बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया बताया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पत्रकारों से बात करते हुए नाथ ने कहा कि ऐसी कोई कमी नहीं है। यह सिर्फ एक माहौल बनाया जा रहा है जिससे कमी का भ्रम पैदा हो रहा है। हाल ही में कई कांग्रेस नेताओं ने ईंधन प्रबंधन को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण आपूर्ति श्रृंखलाओं पर पड़ने वाले दबाव की चेतावनी दी है। हालांकि, उनका यह बयान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के व्यापक रुख से भिन्न प्रतीत होता है, जो पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के मद्देनजर ईंधन आपूर्ति में व्यवधान और बढ़ती कीमतों को लेकर चिंता जता रही है। और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण आपूर्ति श्रृंखलाओं पर दबाव की चेतावनी दी है। इससे पहले दिन में, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार प्रमुख समा राममोहन रेड्डी ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर बुलाई गई।

प्रमुख समाचार



नौरजा चौधरी

पिछले सप्ताह केंद्र सरकार ने अचानक नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण) के तहत संसद और विधानसभाओं में 33 फीसदी महिला आरक्षण के लिए संविधान संशोधन से संबंधित तैयारी शुरू की। उसने इसके लिए विपक्ष से सहयोग मांगा है। बताया यह जा रहा है कि विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाने के बाद संसद का विशेष सत्र बुलाकर संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जायेगा। इसमें कई सारे कदम उठाये जाने की बात कही गयी है। जैसे-संविधान संशोधन से लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 816 हो जाने वाली हैं, जिनमें से 273

सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जायेंगी। इसके अलावा, सरकार ने परिसीमन को 2026-27 के बजय 2011 की जनगणना के आधार पर कराने का फैसला किया है। इसके पीछे तर्क यह है कि नयी जनगणना होने और उसका आंकड़ा आने में इतना समय लग जायेगा कि 2029 के लोकसभा चुनाव तक परिसीमन नहीं हो पायेगा। एक और प्रस्ताव यह है कि संशोधन से राज्यों में सीटों की वृद्धि का अनुपात नहीं बदलेगा। जबकि पहले ऐसा माना जा रहा था कि कम जनसंख्या होने के कारण दक्षिण भारत के राज्यों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस कारण दक्षिण के नेता क्षुब्ध

थे। लेकिन नये प्रस्ताव के मुताबिक, परिसीमन से उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें 80 से बढ़कर अगर 120 हो जायेंगी, तो तमिलनाडु में भी लोकसभा सीटें में वृद्धि इसी अनुपात में होगी। परिसीमन के मुद्दे पर लंबे समय से उत्तर बनाम दक्षिण का न सिर्फ द्वंद छिड़ा हुआ था, बल्कि दक्षिण के राज्यों को लगता था कि जनसंख्या को नियंत्रित रखने का उन्हें दंड दिया जा रहा है, जबकि ज्यादा आबादी वाले उत्तर भारत के राज्यों को लाभ मिलेगा। लेकिन नये प्रस्ताव में यह आशंका दूर हो गयी है। दरअसल, परिसीमन मुद्दे पर



एनडीए में भाजपा के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू तक का रवेया नाराजगी भरा था, और वैसे में, दक्षिण भारत में भाजपा के लिए अपना विस्तार कर पाना कठिन होता, इसलिए 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कराकर दक्षिण की आशंकाओं को दूर करने की

कोशिश है। दरअसल, 19 सितंबर, 2023 को जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण) संसद से पारित हुआ था, तब इसे जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन और 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने की घोषणा की गयी थी। लेकिन अब सरकार ये दोनों कार्य संविधान संशोधन के जरिये करना चाहती है। संविधान संशोधन के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत चाहिए, जो सरकार के पास नहीं है। इसके अलावा, आधे राज्यों को इसे पारित कराना होगा। बेशक मौजूदा राजनीतिक माहौल में इसे पारित कराना आसान नहीं है। लेकिन विपक्षी दल

महिला आरक्षण का विरोध भी नहीं कर पायेंगे। अगर संसद के विशेष सत्र में इस पर मुहर लग जाती है, तो फिर परिसीमन आयोग बैठेगा, और उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले वर्ष तक महिला आरक्षण लागू हो जायेगा। हालांकि यह सवाल उठाया जा रहा है कि महिला आरक्षण को अगर 2011 की जनगणना और परिसीमन के आंकड़ों पर ही लागू करना था, तो इसे पहले भी लाया जा सकता था। लेकिन सरकार अब अचानक यह कदम उठाने जा रही है, तो कुछ सोच-समझकर ही उठा रही होगी। दरअसल, अगले साल तीन राज्यों-उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव, जाहिर है कि भाजपा और

एनडीए के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर अगले साल तक महिला आरक्षण लागू हो जाता है, तो इन तीनों राज्यों में भाजपा को चुनावी लाभ मिलना तय है। फिर 2029 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि फिलहाल यह प्रस्ताव है, और काफी जटिल भी है। कई प्रश्नों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। जैसे परिसीमन के बाद लोकसभा में महिलाओं के लिए 273 सीटें आरक्षित हो जायेंगी। लेकिन ये सीटें किस तरह आरक्षित होंगी, इस बारे में अभी कुछ तय नहीं है। सवाल यह भी है कि परिसीमन जब 2011 की जनगणना के आधार पर ही होना है।

बस्तर से नक्सल उन्मूलन: सरकार की नीतियों से मिली सफलता, जानिए कौन बना बड़ा गेमचेंजर

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवाद के सिमटते ही उम्मीदों की नई रोशनी आई है।फोर्स और सरकार के समन्वय ने वो कर दिखाया है जिसका पूरा होना एक सपने के सच होने जैसा है।आज से दो साल पहले तक ये कौन कह सकता था कि बस्तर को जिस समस्या सबसे ज्यादा दर्द दिया है उसका इलाज इतना जल्दी हो जाएगा। नक्सलवाद के नासुर का ऑपरेशन जिस तरह से फोर्स ने किया है उसके दोबारा फैलने की उम्मीद अब बहुत कम बची है।

ऑपरेशन के बाद सरकार की ओर से जो एंटीबायोटिक दी जा रही है उससे बस्तर की ना सिर्फ जल्दी रिकवरी होगी,बल्कि वो पहले से ज्यादा मजबूत और



स्वस्थ बनकर अपनी पहचान पूरी दुनिया को बताएगा। बस्तर में नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन 31 मार्च 2026 तय की गई थी। इसके बाद से जिस तरह की तेजी और विकास को लेकर रोडमैप तैयार किया गया उसका नतीजा आज पूरी दुनिया के सामने है। आज नक्सलियों का पोषण करने वाले या तो मिट्टी में मिल चुके हैं या फिर अपने भविष्य की तस्वीर से घबराकर हथियार डाल चुके हैं।नक्सलियों के ब्रेन या तो अब डेड हो चुके हैं या फिर हथियार

और टीम समेत समाज की मुख्यधारा में शामिल हो चुके हैं। आईए आपको बताते हैं कि वो तीन कारण कौन से हैं जिनके कारण नक्सलवाद की जड़ें कमजोर होनी शुरू हुईं। वहीं नक्सल मामलों के जानकर एवं वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता ने बताया कि बस्तर से नक्सलवाद की समाप्ति के लिए तीन बड़े कारण बताए हैं। पहला कारण 2014-15 में बनी राष्ट्रीय नीति है। जिसका नाम समाधान रखा गया था। इस नीति के तहत

माओवादियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाई गई और हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जाएगा। इलाके में विकास कार्यों को बढ़ाया गया। साथ ही नक्सल प्रभावित इलाकों के ग्रामीणों से बेहतर समन्वय स्थापित किया गया। इससे ग्रामीणों को नक्सलियों के संपर्क से दूर किया गया। इतिहास में पहली बार ऐसी नीति बनी। इसके बाद बेहतर अनुशरण करके ऑपरेशनस किए गए। जिसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है। नक्सल मामलों के जानकार मनीष गुप्ता ने बताया कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। केंद्र सरकार की नोटबंदी ने माओवादियों की कमर तोड़ी है।

अंतर्राष्ट्रीय साइबर गिरोह के दो गुर्गे गिरफ्तार

रायगढ़। रायगढ़ पुलिस ने एक सेवानिवृत्त शिक्षक से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 23 लाख रुपये से अधिक की ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय साइबर गिरोह के दो सदस्यों को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने स्वयं को सीबीआई अधिकारी बताकर पीड़ित से 12 किस्तों में रकम हस्तांतरित कराई थी। पुसौर थाना क्षेत्र के ग्राम जतरी निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक गरुड़ सिंह पटेल ने 11 नवंबर 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 10 अक्टूबर 2025 को अनजान व्यक्तियों ने फोन कर खाते की जांच में सहयोग मांगा। आरोपियों ने धमकाकर 25 से 29



अक्टूबर 2025 के बीच यूपीआई, पेटीएम और आरटीजीएस के माध्यम से 23 लाख 28 हजार 770 रुपये अलग-अलग खातों में डलवा लिए। जांच के बाद पुलिस को आरोपियों के बेंगलुरु में होने की जानकारी मिली। पुलिस टीम ने विगनेश प्रकाश और स्टीफन थॉमस को बेंगलुरु से पकड़ा। पूछताछ में पता चला कि दुबई में रहने वाला फिरोज खान उर्फ डोमिनिक इस गिरोह का मुख्य सरगना है।

बहू पर प्रताड़ना का आरोप, सास और पति ने मांगी इच्छामृत्यु

सूरजपुर। लटोरी निवासी शकुंतला पाण्डेय अपने बेटे के साथ बुधवार को इच्छामृत्यु की मांग का आवेदन लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। महिला ने आरोप लगाया कि उनकी बहू रागिनी मिश्रा उन्हें लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है और पैसों की मांग कर रही है, जिससे परेशान होकर वे अब मौत चाहते हैं।

शकुंतला पाण्डेय का कहना है कि उनकी बहू ने 3 अक्टूबर 2021 को उनपर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए घर छोड़ दिया था, जिसके चलते उनके बेटे वेद प्रकाश और पूरे परिवार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब लगभग 5 साल बाद बहू दोबारा घर लौट आई है।



लेकिन इसके बाद भी घर का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। पीड़िता का आरोप है कि बहू वापस आकर फिर से आर्थिक और मानसिक दबाव बना रही है। इसी से तंग आकर उन्होंने प्रशासन से या तो न्याय दिलाने या फिर इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की मांग की है। घर में बड़े अधिकारियों का फोन आता है, लटोरी पुलिस भी घर पहुंचती है, फोन करते हैं। वेदप्रकाश ने लटोरी चौकी प्रभारी पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लटोरी चौकी प्रभारी घर में आकर

तेंदुआ खाल मामले में हाई कोर्ट ने तीनों आरोपियों को किया बरी

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई

कोर्ट ने एक अहम फैसले में वन्यजीव तस्करी के मामले में दोषी ठहराए गए तीन आरोपियों को बरी कर दिया है। यह फैसला न्यायमूर्ति राधाकिशन अग्रवाल की एकल पीठ ने सुनाया है। यह मामला सूरजपुर जिले का है, जहां पुलिस ने 23 जनवरी 2014 को सूचना के आधार पर तीन आरोपी राजेश तिवारी, सुनील सिंह और रामचंद्र खैरवार को मोटरसाइकिल पर जाते समय रोका था। तलाशी के दौरान उनके पास से तेंदुए की खाल बरामद होने का दावा किया गया। इस आधार पर आरोपियों के खिलाफ वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972 की धारा 51(1-ए) के तहत मामला दर्ज किया गया और ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा और



10,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया था। बाद में सेशन कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने साक्ष्यों की गहन समीक्षा के बाद कई गंभीर खामियां पाईं। जलत की गई तेंदुए की खाल को सील नहीं किया गया था। मालखाना का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। यह स्पष्ट नहीं हुआ कि खाल सुरक्षित रूप से रखी गई थी या नहीं। स्वतंत्र गवाहों ने भी जखती या पंचनामा का समर्थन नहीं किया। जांच अधिकारी के जयान में भी कई विरोधाभास पाए गए। खाल को कब और कैसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया।

दरवाजे खिड़कियां तोड़ते हैं। वे कहते हैं कि उनकी एक बच्ची है, जिसे वे अपने पास रखना चाहते हैं। प्रताड़िता से तंग आकर मां बेटे ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। मां बेटे की इच्छामृत्यु की मांग पर सूरजपुर एसडीओपी अभिषेक पैकरा ने बताया कि बहू ने अपने पति और सास पर प्रताड़ना का आरोप लगाया, जिसका केस सूरजपुर कोर्ट में चल रहा है। इसके अलावा भरण पोषण का मामला गृह न्यायालय में चल रहा है। लगभग 4 साल के बाद बहू अपने ससुराल में रहने के लिए आई है, जहां सास शकुंतला पांडेय ने बहू को रखने से मना कर दिया। सास ने बहू पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए इच्छा मृत्यु की मांग की है।

धमतरी पुलिस द्वारा गुमशुदा व्यक्तियों की वापसी के लिए अभियान

धमतरी। गुमशुदा लोगों की खोज के उद्देश्य से ऑपरेशन तलाश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय धमतरी के सभाकक्ष में जिला स्तरीय समन्वय बैठक आयोजित की। बैठक पुलिस अधीक्षक धमतरी के निदेशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र कुमार पांडेय ने ली। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा करते हुए अभियान की रणनीति, कार्यप्रणाली एवं जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की ठोस कार्ययोजना तैयार की गई।

बैठक में बताया गया कि 01 से 30 अप्रैल तक जिले में 30 दिवसीय विशेष अभियान

ऑपरेशन तलाश संचालित किया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य लंबित गुमशुदगी प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करना, गुमशुदा व्यक्तियों की खोजबीन करना और उन्हें सुरक्षित उनके परिजनों से मिलाना है।

सभी थाना क्षेत्रों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर विशेष पुलिस टीमों का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार, सार्वजनिक स्थलों, होटल-लॉज, ढाबों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में सघन जांच एवं तलाशी अभियान चलाया जाएगा। खोज प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए सीसीटीवी फुटेज विश्लेषण, तकनीकी साक्ष्य,

साइबर सेल की सहायता और अन्य जिलों एवं राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर इंटर-स्टेट स्तर पर ट्रैकिंग को मजबूत किया जाएगा।

महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, श्रम एवं समाज कल्याण विभाग के सहयोग से बाल संरक्षण, बाल श्रम उन्मूलन और पुनर्वास संबंधी संयुक्त कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में पुलिस विभाग के डीएसपी, एसजेपीयू, डीसीबी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र कुमार पांडेय ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिया।

छत्तीसगढ़
प्रमुख समाचार

खरीफ और रबी सीजन के लिए जिला स्तरीय कृषि नियंत्रण कक्ष स्थापित

जगदलपुर। जिले के किसानों के लिए कृषि विभाग के द्वारा आगामी खरीफ और रबी सीजन 2026-27 के लिए जिला स्तरीय कृषि नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर दी गई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य किसानों को उन्नत बीज, गुणवत्तापूर्ण उर्वरक और कीटनाशक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, साथ ही बाजार में खाद-बीज की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और ऊंचे दामों पर बिज्नी की रोकथाम करना है। इसके अतिरिक्त फसलों में लगने वाले कीट और व्याधियों के उचित प्रबंधन के लिए विशेषज्ञ इस केंद्र के माध्यम से किसानों को समय-समय पर तकनीकी सलाह भी प्रदान करेंगे। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिकारियों को एक समर्पित टीम तैनात की गई है, जिसमें सहायक संचालक कृषि लखनधर दीवान (7000258043) को नोडल अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बलराम प्रसाद (9425262714) को सहायक नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी सहायता के लिए केके झा (9424283895), से संपर्क कर सकते हैं।

कलेक्टर छिकारा ने किया सेवानिवृत्त कर्मियों का सम्मान

जगदलपुर। शासकीय सेवा की एक लंबी और कर्तव्यनिष्ठ यात्रा पूरी कर सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए एकलेक्टोरेट के आस्था कक्ष में एक गरिमामयी विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर आकाश छिकारा ने सेवानिवृत्ति प्राप्त कर रहे 09 अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामनाएं देते हुए उन्हें शॉल, श्रीफल से सम्मानित किया। प्रशासन की संवेदनशीलता का परिचय देते हुए कलेक्टर ने सभी सेवानिवृत्त कर्मियों को उसी समय पेंशन भुगतान आदेश भी प्रदान किए, ताकि सेवा के बाद उनकी आगामी राह सुगम हो सके। समारोह को संबोधित करते हुए श्री छिकारा ने भावुक शब्दों में कहा कि आप सभी ने विभिन्न विभागों में रहते हुए अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय लोक सेवा और जनहित के कार्यों में व्यतीत किया है, जिसके लिए प्रशासन और जनता सदैव आपके आभारी रहेंगे। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि शासकीय सेवा से निवृत्ति केवल एक औपचारिक पड़ाव है।

स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित

कोंडगांव। जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम विद्यालयों में सत्र 2026-27 में प्रवेश के संबंध में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जायकोटपाड़ा कोण्डगांव, महामता गांधी वाई कोण्डगांव, दहिकोंगा, मर्दापाल, लंजोड़ा, फरसगांव, कोनगुड, धनोरा, केशकाल, विश्रामपुरी, बडेराजपुर, बांसकोट, शामपुर एवं माकड़ी तथा हिन्दी माध्यम विद्यालय, तहसीलपाड़ा कोण्डगांव, बम्हनी, लुभा, बडेडोंगर, बहीगांव एवं खालेमुरवेण्ड, प्रबंधन एवं संचालन समिति कोण्डगांव जिला कोण्डगांव के अधीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी / हिन्दी माध्यम विद्यालयों में प्रवेश हेतु आवेदन 10 अप्रैल से 05 मई तक ऑनलाईन एवं ऑफलाईन पद्धति से किया जा सकता है। अधिक आवेदन की स्थिति में लाटरी के माध्यम से सीट का आबंटन दिनांक 06 मई से 10 मई 2026 तक किया जायेगा, साथ ही प्रवेश से संबंधित अन्य आवश्यक कार्यवाही दिनांक 11 मई से 15 मई 2026 तक सम्पूर्ण विद्यालयों को पूर्ण किया जाना सुनिश्चित है।

शिवरीनारायण के महानदी में नाविकों के 2 गुट

जांजगीर चांपा। जिले के शिवरीनारायण नगर पंचायत में 26 मार्च से नाविक अनिश्चित कालीन हड़ताल पर बैठे हैं. लकड़ी की नाव का संचालन होना और फाइबर बॉडी नाव के संचालन पर रोक लगाना आंदोलन की मुख्य वजह है। प्रदेश में शिवरीनारायण का नाम प्रमुख धार्मिक स्थल के साथ पर्यटन के क्षेत्र में उभरता जा रहा है, इसके कारण अब नाविकों में कॉम्पिटिशन भी बढ़ता जा रहा है। अब पारंपरिक लकड़ी के सस्ते नाव के अलावा अत्याधुनिक फाइबर बॉडी हाई स्पीड महंगे नाव के आने से विवाद गहरा गया है। शिवरीनारायण में नाविकों और नगर पंचायत के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। दरअसल नगर पंचायत ने महानदी में लकड़ी के 45 बड़े नाव संचालन के लिए नाविकों को आदेश दिया है। साथ ही फाइबर बॉडी के नाव पर रोक लगा कर उसके मोटर जब्त कर लिए हैं। इसके कारण नाविक दो गुट में बंट गए हैं। एक गुट 26 मार्च से अनिश्चित कालीन हड़ताल में बैठ गया है, ये न नाविकों का गुट है जो अपनी फाइबर बॉडी नाव को भी नदी में चलाने की अनुमति मांग रहा है।

हनुमान जन्मोत्सव पर निकली शोभायात्रा शोभायात्रा

राजनंदागांव। राजनंदागांव में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर भव्य शोभायात्रा निकाली गई। म्युनिसिपल स्कूल से शुरू हुई यह यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरी, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान नगर का वातावरण भक्तिमय हो गया। शोभायात्रा का शुभारंभ म्युनिसिपल स्कूल के प्रांगण से हुआ और यह शहर के कई चौक-चौराहों से होते हुए महावीर चौक पर समाप्त हुई। इस आयोजन में पूर्व महावीर मधुसूदन यादव, झमन देवांगन, राजू वैष्णव, राजेंद्र यादव, पंकज गुप्ता शामिल हुए। यात्रा के दौरान जय हनुमान और जय श्रीराम के नारे गूंजते रहे, जब शोभायात्रा मम मंदिर चौक पहुंची, तो हिंदू गणगण मंच के कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं ने फूलों की वर्षा कर हनुमान जी की झांकी का स्वागत किया। इस साल की शोभायात्रा में महिलाओं की भागीदारी भी महत्वपूर्ण रही। बड़ी संख्या में महिलाएं पारंपरिक परिधानों में शामिल हुईं। महिला इकाई द्वारा पूजा-अर्चना व भक्ति गीत गाकर अपनी आस्था व्यक्त की।

नक्सल मुक्त क्षेत्रों को अब सुशासन की आवश्यकता

विपिन पल्ल्वी

1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में हुए विद्रोह के बाद से, वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद अक्सर हत्याओं, मुठभेड़ों और हिंसा की खबरों के साथ सुर्खियों में बना रहा है। एक समय ऐसा था जब देश के एक चौथाई से अधिक हिस्से-पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, जिसे ‘रेड कॉरिडोर’ कहा जाता था-में नक्सलियों का दबदबा था। जहां सुरक्षा बलों के सदस्यों, नक्सलियों और आम नागरिकों सहित हजारों लोग मारे गए या घायल हुए, वहीं इन क्षेत्रों में, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में विकास कार्य लगभग ठप्प हो गया था। नक्सलियों ने अपनी समानांतर सरकार बना ली थी और वे सड़कों के निर्माण या बुनियादी ढांचे के विकास को अनुमति नहीं देते थे, ताकि सरकार और सुरक्षा बलों को दूर रखा जा सके। एक लंबी अवधि तक सरकार इस खतरे से लड़ती रही और नक्सलियों के प्रभाव को मुख्य

रूप से छत्तीसगढ़ तक सीमित करने में सफल रही। इस आंदोलन के खिलाफ एक निर्णायक अभियान 2006 में शुरू हुआ, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने घोषणा की कि माओवादी हिंसा ‘आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा’ है। हालांकि, वर्तमान सरकार द्वारा इसे बड़ा बढ़ावा दिया गया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च, 2026 तक देश को ‘नक्सल मुक्त’ बनाने की समय सीमा तय की। नक्सली हिंसा से छुटकारा पाने के अपने संकल्प में प्रभावी कदम उठाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को श्रेय दिया जाना चाहिए। अमित शाह ने अपनी निर्धारित समय सीमा से एक दिन पहले देश को ‘नक्सल मुक्त’ घोषित करते हुए बताया कि पिछले 3 वर्षों में 4,839 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, 706 मारे गए और 2,218 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।।”2024 को शुरुआत में माओवादियों की केंद्रीय समिति और पोलिट ब्यूरो में 22 सदस्य थे। आज एक भी नहीं है।” उन्होंने कहा कि नक्सलवाद ‘लगभग खत्म हो चुका है’ और



माओवादियों के खिलाफ बल प्रयोग का बचाव करते हुए कहा कि जो गोलियां चलाते हैं, उन्हें गोतियों से ही जवाब दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि नक्सलियों द्वारा इस्तेमाल किए गए 92 प्रतिशत हथियार पुलिस के शस्त्रागार से लूटे गए थे। जहां हिंसा को समाप्त करने के संकल्प के लिए सरकार को श्रेय दिया जाना चाहिए, वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.) के नेतृत्व में अर्धसैनिक बलों के

साथ-साथ संबंधित राज्यों के पुलिस बलों और अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी.ए.पी.एफ्स) जैसे सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी.) और सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.) ने हिंसा से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहां तक कि भारतीय सेना और वायुसेना भी नक्सलियों को बाहर निकालने के लिए कुछ ऑपरेशनों में शामिल हुईं। लेकिन इसका श्रेय उन अधिकारियों और श्रमिकों को भी जाता है, जो माओवादियों की धमकियों के बावजूद सड़कें बिछाने और बुनियादी ढांचे के निर्माण में लगे रहे, जिसने अंततः पासा पलट दिया और माओवादियों ने जंगलों में अपना समर्थन खो दिया। मडवो हरिदाम, नरमला केशव राव, गणेश उइके, सत्यनारायण रेड्डी और रामचंद्र रेड्डी जैसे शीर्ष माओवादी नेताओं के मुठभेड़ों में मारे जाने और मल्लो जुला वेणुगोपाल राव, देवा बरसे और देवूजी जैसे नेताओं के आत्मसमर्पण ने माओवादियों के नेतृत्व को लगभग

समाप्त कर दिया है। अब केवल दो शीर्ष नेता-मुप्पला लक्ष्मण राव (गणपति) और मिसिर बेसरा (सागर) का आत्मसमर्पण करना बाकी है। सुरक्षा बलों का मानना ​​है कि वे जल्द ही ऐसा कर देंगे। हालांकि, सुरक्षा बलों की इस सफलता के बाद, अब नागरिक सरकार की बारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि स्थिति फिर से न निगड़े। नक्सलवाद के पुनरुत्थान को रोकने के लिए, सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में समावेशी विकास, बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार के अवसरों को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसे स्थानीय संस्थानों को मजबूत, कानून-व्यवस्था में सुधार और भ्रष्टाचार को दूर करना चाहिए। एक अन्य महत्वपूर्ण उपाय आत्मसमर्पण करने वाले केडरों को सहायता प्रदान करना होगा, जिसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता शामिल है। साथ ही, सरकार अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकती और उसे नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमता को बढ़ाना चाहिए।

संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल डेका ने हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर की पूजा-अर्चना

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने गुरुवार



को हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर नर्मदा कुंड हनुमान मंदिर स्टेशन चौक एवं सर्व धर्म हनुमान मंदिर रेल्वे स्टेशन कैम्पस रायपुर में विधिवत पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि, खुशहाली और प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना कर आशीर्वाद लिया।

धमतरी के विद्यार्थियों ने किया लोकभवन का भ्रमण : राज्यपाल से की मुलाकात

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका की पहल



पर प्रदेश के सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय ‘‘लोकभवन‘‘ की कार्यप्रणाली से अवगत कराने और यहां की कार्यालयीन गतिविधियों से जनसामान्य को जोड़ने के उद्देश्य से लोकभवन का भ्रमण कराया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को डी.पी.एस. स्कूल के विद्यार्थियों ने लोकभवन का भ्रमण किया और राज्यपाल श्री रमेन डेका से आत्मीय मुलाकात की। श्री डेका ने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए उन्हें जरूरी मार्गदर्शन प्रदान किए। श्री डेका ने कहा कि विद्यार्थी जीवन बहुत सुंदर होता है। इसका सदुपयोग करें तभी सफलता मिलेगी। जीवन के सभी निर्णयों को सोच-समझकर उठे दिमाग से लेना चाहिए। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। हर विद्यार्थी डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकता बल्कि अनेक क्षेत्र हैं जहां अपना कैरियर बना सकते है। डी.पी.एस. स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले 51 छात्र और 25 छात्राओं की टोली ने अपने शिक्षक-शिक्षिकाओं के साथ लोकभवन का भ्रमण कर यहां की ऐतिहासिक व कार्यालयीन महत्ता को जाना और समझा। उन्हें लोकभवन परिसर स्थित छत्तीसगढ़ मंडपम, उर्दती परिसर, कन्हार परिसर, डिस्पेंसरी, सचिवालय की विभिन्न शाखाओं और हरे-भरे उद्यान का भ्रमण कराया गया और इन स्थानों के संबंध में विस्तृत जानकारी भी प्रदान की गई। भ्रमण एवं अवलोकन के बाद विद्यार्थियों ने बताया कि लोकभवन में आकर उन्हें नया अनुभव हो रहा है। पहली बार वे राज्यपाल से मिले हैं साथ ही यहां की संरचना, हरियाली देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई है।

उद्योग भवन सर्विस रोड व पुरेना मुख्य मार्ग अतिक्रमणमुक्त

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के



निर्देशानुसार राजधानी रायपुर में सुगम एवं व्यवस्थित यातायात सुनिश्चित करने के लिए टीम प्रहरी अभियान के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में नार पालिक निगम रायपुर द्वारा आयुक्त श्री विश्वदीप के नेतृत्व में जोन क्रमांक 10 अंतर्गत उद्योग भवन सर्विस रोड एवं पुरेना मुख्य मार्ग को अतिक्रमणमुक्त करने व्यापक अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान संबंधित विभागों एवं यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने सर्विस रोड एवं मुख्य मार्ग पर किए गए अतिक्रमण को हटाते हुए लगभग 5-6 ठेलों एवं गुमटियों को हटाय। वहीं लगभग 30-35 ठेला एवं गुमटी संचालकों को 24 घंटे के दौरान स्वयं अतिक्रमण हटाने की सख्त समझाइश दी गई है। प्रशासन द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि सड़क एवं सर्विस रोड पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण स्वीकार्य नहीं होगा। निर्धारित समय सीमा में अतिक्रमण नहीं हटाने पर संबंधित सामग्री की जब्त, जुर्माना एवं सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित अतिक्रमणकर्ताओं की होगी।

केंद्रीय गृह मंत्री शाह से सांसद पांडेय ने की मुलाकात

रायपुर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री



अमित शाह से भाजपा मुख्य प्रवक्ता एवं सांसद संतोष पांडेय ने दिल्ली प्रवास के दौरान मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री शाह से सांसद पांडेय ने बस्तर में नक्सल मुक्त अभियान को लेकर विस्तार से चर्चा की। सांसद पांडेय ने बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री शाह का आधार व्यक्त करते हुए कहा कि बस्तर में नक्सलवाद के समापन के बाद एक नए बस्तर का उदय हुआ है जो बस्तर को वैश्विक पहचान दिलाएगा।

राजधानी/छत्तीसगढ़

जगगी हत्याकांड मामले : हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

अमित जोगी को तीन हफ्ते में करना होगा सरेंडर

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रामावतार जगगी हत्याकांड में हाईकोर्ट ने अमित जोगी को दोषी करार दिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने उन्हें तीन हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद वर्मा की स्पेशल डिवीजन बेंच ने यह अहम फैसला सुनाया है।

इससे पहले कोर्ट ने सबूतों के अभाव में अमित जोगी को बरी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस पूरे मामले को हाईकोर्ट में रीओपन किया गया। मामले की जांच करने वाली एजेंसी सीबीआई ने कोर्ट में 11 हजार पन्नों की रिपोर्ट पेश की थी। इसी विस्तृत जांच रिपोर्ट के आधार पर अमित जोगी पर भी चार्ज लगाए गए थे और आज अंतिम सुनवाई के बाद



उन्हें दोषी माना गया है। अब उन्हें तीन हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा, जिसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

मामले की सुनवाई के दौरान स्व. रामअवतार जगगी के बेटे सतीश जगगी ने कोर्ट को बताया कि उनके पिता की हत्या एक राजनीतिक साजिश थी। सीबीआई ने 11 हजार पन्नों की चार्जशीट पेश की थी, जिसमें हत्या से जुड़े पर्याप्त सबूत शामिल हैं। इधर

अप्रत्याशित है। उन्होंने कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है।

हाईकोर्ट के फैसले पर अमित ने कहा- मेरे साथ अन्याय हुआ

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित राम अवतार जगगी हत्याकांड मामले में अमित जोगी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए तीन हफ्ते में सरेंडर करने

का आदेश दिया है। वहीं इस मामले में अमित जोगी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि आज उच्च न्यायालय ने बिना सुनवाई का अवसर दिए मेरे विरुद्ध सीबीआई की अपील को मात्र 40 मिनट में स्वीकार कर लिया। मुझे खेद है कि जिस व्यक्ति को अदालत ने दोषमुक्त किया था, उसे बिना सुनवाई का एक भी अवसर दिए दोषी करार दिया गया। यह अप्रत्याशित है।

अमित जोगी ने कहा, अदालत ने मुझे 3 सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का समय दिया है। मुझे लगता है कि मेरे साथ गंभीर अन्याय हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय से मुझे न्याय अवश्य मिलेगा। मैं न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास रखता हूं। मैं पूर्ण शांति, आस्था और धैर्य के साथ आगे बढ़ रहा हूं। सत्य की जीत अवश्य होगी।

शराब घोटाला : लखमा समेत 59 लोगों की हुई पेशी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आज बड़ा अपडेट सामने आया है। मामले से जुड़े कुल 59 आरोपियों को प्रवर्तन निदेशालय (धष्ट) की विशेष कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों की मौजूदगी में कोर्ट की कार्यवाही पूरी की गई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

बता दें कि कोर्ट में धारा 88 के तहत आरोपियों के बयान दर्ज किए गए। इस दौरान पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी कोर्ट में पेश हुए। वहीं इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल, सौम्या चौरसिया और निरंजन दास समेत आबकारी विभाग से



जुड़े अन्य अधिकारी भी अदालत में उपस्थित रहे। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जानकारी के अनुसार, अदालत इस मामले में कुछ ही देर में अपना फैसला सुना सकती है। इस हाई-प्रोफाइल मामले में सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसमें कई बड़े नाम शामिल हैं और इसका राजनीतिक असर भी देखने को मिल सकता है।

लोक निर्माण विभाग के लिए ऐतिहासिक रहा बीता वित्तीय वर्ष

993 कार्यों के लिए 9129 करोड़ से अधिक की दी स्वीकृति

रायपुर। लोक निर्माण विभाग के लिए विगत 31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष 2025-26 ऐतिहासिक रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में विभाग ने राज्य के निर्माण के बाद से अब तक सबसे ज्यादा कार्यों और राशि के प्रशासकीय स्वीकृति के आदेश जारी किए हैं। विगत वित्तीय वर्ष में विभाग द्वारा कुल 993 कार्यों के लिए 9129 करोड़ 18 लाख रुपए मंजूर किए



गए हैं। यह राशि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के बाद से किसी एक वर्ष में स्वीकृत सर्वाधिक राशि के दोगुने से भी ज्यादा है। वर्ष 2025-26 में मंजू्र की गई राशि 2024-25 में स्वीकृत 2589 करोड़ 89 लाख रुपए की तुलना में तिगुने से भी ज्यादा है, जबकि कार्यों की संख्या दोगुने से भी अधिक है।

हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में लोक निर्माण विभाग ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की मांगों, जरूरतों और जन आकांक्षाओं को देखते हुए उ्प मुख्यमंत्री तथा विभागीय मंत्री श्री अरुण साव के निर्देश पर 1925 नए कार्यों को शामिल करते हुए इनके लिए 2287 करोड़ रुपए के प्रावधान किए थे। पिछले वर्ष के बजट में राज्य निर्माण के बाद से सर्वाधिक संख्या में नए कार्यों के प्रस्ताव शामिल किए गए थे। बजट में शामिल नए कार्यों को प्राथमिकता में रखते हुए बड़ी संख्या में इनकी मंजूरी के आदेश जारी किए गए हैं।

उ्प मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने प्रदेशभर में सड़कों और पुलों के कार्यों को गति देने प्रस्तावित

बजरंगबली की गदा कांग्रेस पर चल रही, पार्टी की विचारधारा समाप्ति की ओर : रामविचार नेताम

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कृषि

मंत्री रामविचार नेताम ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बजरंगबली की गदा अब कांग्रेस पर चल रही है और उसका असर साफ दिखाई दे रहा है। राम मंदिर पहुंचे नेताम ने प्रदेशवासियों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भगवान राम के आतिथ्य को स्वीकार नहीं किया, उसी दिन से उसका पतन तय हो गया था। उन्होंने दावा किया कि वीर बजरंगबली की गदा कांग्रेस पर पड़ चुकी है और उसकी विचारधारा पूरी तरह समाप्त होने की ओर है। कांग्रेस को अब आत्मसंशोधन कर भाजपा में शामिल हो जाना चाहिए।

मंत्री नेताम ने भगवान से प्रार्थना की कि देश और प्रदेश से अन्याचार का अंत हो। साथ ही उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ चल रही कार्रवाई को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में नक्सलियों के खاتم्वे की शुरुआत



छत्तीसगढ़ से हो चुकी है। देश में राम राज्य स्थापित करने का संकल्प पूरा किया जा रहा है और यह बजरंगबली के आशीर्वाद के बिना असंभव था।

कांग्रेस की संगठनात्मक गतिविधियों पर तंज कसते हुए नेताम ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपने ही नेताओं पर भरोसा नहीं है, इसलिए वह अपने नवनि्युक्त जिला अध्यक्षों के कामों की मॉनिटरिंग कर रही है। नेताम के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज होने के आसार हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ख़ाद

संकट का दावा कर रही है। इस पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा, कांग्रेसियों को कांग्रेस से संकट है।

देश में ख़ाद का कोई संकट नहीं है। संकट इसलिए है क्योंकि बिचौलियों का समर्थन कांग्रेस करते आई है। सरकार बहुत सख्ती करेगी, ताकि कोई ख़ाद का भंडारण न कर सके। कांग्रेस ने नक्सलमुक्त गांवों के लिए स्पेशल पैकेज की मांग की है। इस पर नेताम ने कहा, सब देंगे, लेकिन उनके पेट में अभी से दर्द क्यों हो रहा है. चिंता न करे हम सब ठीक करेंगे।

आज से महादेव घाट में वॉलीबॉल का महासंग्राम, मृणत करेंगे उद्घाटन

■ देश-विदेश के खिलाड़ी दिखाएंगे दम

रायपुर। हटकेश्वरनाथ वॉलीबॉल संघ, रायपुर द्वारा 3 से 5 अप्रैल तक महादेव घाट स्थित हटकेश्वरनाथ वॉलीबॉल ग्राउंड में 5वीं ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2026 का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता का उद्घाटन 3 अप्रैल, शुक्रवार को शुरू 10 बजे विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेश मृणत के मुख्य आतिथ्य में होगा। इस अवसर पर मनोज वर्मा, महेन्द्र औषध (पार्षद द्वय) मोहम्मद अकरम खान, अनुराग राठी सरंक्षक, मंगलेस्वर सिंह,जितेन्द्र सिंह, मार्तंड सिंह सचिव, रमाकांत निषाद सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे।

प्रतियोगिता में मास्टर्स 40+ वर्ग के साथ ओपन गर्ल्स स्पर्धा भी होगी। मास्टर्स वर्ग में दुबई, उत्तर प्रदेश, केरल, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, ओडिशा, चंडीगढ़, कोरबा, रायपुर और मॉर्निंग क्लब की टीमें



भाग लेंगी, जबकि महिला वर्ग में पुणे, हरियाणा, कोलकाता, दिल्ली, आगरा, एसएआई रायपुर और भिलाई की टीमें उतरेंगी।

आयोजकों के अनुसार, प्रतियोगिता में भाग लेने वाली कई टीमों में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध खिलाड़ी शामिल रहेंगे। मास्टर्स वर्ग में प्रथम पुरस्कार 71,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 51,000 रूपए। ओपन गर्ल्स वर्ग में प्रथम पुरस्कार 31,000 रुपए तथा द्वितीय वर्ग में 21,000 रुपए और शौलड रखा गया है। आयोजन के बारे जानकारी अध्यक्ष सैयद अनवर अली ने दी है।

कुंवरगढ़ महोत्सव में छत्तीसगढ़ी कला-संस्कृति की धूम

■ कलाकारों की प्रस्तुतियों पर झूमे दर्शक

रायपुर। ऐतिहासिक कुंवरगढ़ महोत्सव के दूसरे दिन आयोजित सांस्कृतिक संध्या में छत्तीसगढ़ी लोक कला, संगीत एवं हास्य का मनमोहक संगम देखने को मिला। विभिन्न कलाकारों की आकर्षक प्रस्तुतियों ने पूरे पंडाल को तालियों की गूड़गुड़ाहट से गुंजायमान कर दिया। कार्यक्रम का शुरुआत प्रसिद्ध गायक विवेक शर्मा की ऊर्जावान प्रस्तुति से हुई। उन्होंने अपने लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुति देकर दर्शकों में उत्साह का संचार किया। इसके पश्चात लोक गायिका गरिमा दिवाकर ने भक्ति और लोक संगीत का सुंदर समन्वय प्रस्तुत करते हुए वातावरण को आध्यात्मिक रंग में रंग दिया। उभरती कलाकार चम्पा निषाद ने भी अपने मधुर गीतों से दर्शकों का मन मोह लिया। सांस्कृतिक संध्या में हास्य



कलाकार पप्पू चंद्राकर ने अपनी प्रस्तुति से विशेष आकर्षण बटोरा। उन्होंने दैनिक जीवन से जुड़े प्रसंगों पर हास्य व्यंग्य प्रस्तुत कर दर्शकों को खूब गुदगुदाया।महोत्सव के तीसरे एवं अंतिम दिन भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के ख्यातिप्राप्त कलाकार अनुराग शर्मा, छाया चंद्राकर, कंचन जोशी, शैलेश साव एवं रेखा जलक्षत्ररी अपनी प्रस्तुतियां देंगे, जिसे लेकर क्षेत्रवासियों में विशेष उत्साह है।

कुंवरगढ़ महोत्सव के माध्यम से क्षेत्र की समृद्ध लोक संस्कृति, परंपरा एवं कला को प्रोत्साहन मिल रहा है तथा बड़ी संख्या में लोग इस आयोजन से जुड़ रहे हैं। इस अवसर पर राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, धरसीवां विधायक श्री अनुज शर्मा, अभनपुर विधायक श्री इंद्र कुमार साहू, जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं आमजन उपस्थित रहे।

महतारी वंदन योजना बनी संबल, बदली जिंदगी

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बदलाव की नई कहानी लिख रही है। बलरामपुर जिले के विकासखंड वाड्डफनगर के ग्राम रघुनाथनगर की निवासी श्रीमती मानकुंवर इसकी उदाहरण हैं, जिनके लिए यह योजना आज आर्थिक संबल और आत्मविश्वास का आधार बन गई है।

महतारी वंदन योजना के तहत श्रीमती मानकुंवर को प्रतिमाह 1000 रुपये की नियमित सहायता राशि प्राप्त हो रही है। पहले जहां परिवार की छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करना भी कठिन था, वहीं अब यह राशि उनके दैनिक जीवन को सहज बना रही है। राशन, बच्चों की आवश्यकताएं और घरेलू खर्च जैसे जरूरी काम अब बिना किसी अतिरिक्त दबाव के पूरे हो पा रहे हैं।

अपर मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अंतर्विभागीय समिति की बैठक सम्पन्न

छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग से तेलंगाना व अन्य प्रांतो में प्रवासित परिवारों के लिए पुर्नवास के लिए बनेगी कार्ययोजना

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग के ऐसे विस्थापित परिवार जो किन्ही कारणों बस्तर संभाग के सीमावर्ती तेलंगाना एवं आन्ध्रप्रदेश में प्रवासित हैं, ऐसे परिवारों के पुनर्वास की कार्ययोजना बनायी जा रही है। मंत्रालय महानदी भवन में गुरुवार को अपर मुख्य सचिव गृह श्री मनोज कुमार पिंगुआ की अध्यक्षता में पुनर्वास हेतु गठित राज्य स्तरीय अंतर्विभागीय समिति की प्रथम बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के संबंध में कार्ययोजना तैयार करने विस्तार से विचार-विमर्श हुआ।

बैठक में बताया गया कि जिला दंतेवाड़ा, सुकमा एवं बीजापुर के लोग तेलंगाना एवं आन्ध्रप्रदेश राज्य में प्रवासित हो गए है। इसके लिए प्रवासित परिवारों की ओर से राष्ट्रीय जनजातीय आयोग में याचिका दायर किया गया है। इसके तहत माननीय आयोग द्वारा एक माह के भीतर सर्वे कर प्रवासित परिवारों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश



दिए गए हैं। इसके परिपालन में बस्तर संभाग के संभागायुक्त द्वारा एक समयबद्ध कार्यक्रम के तहत कलेक्टर दंतेवाड़ा, सुकमा एवं जिला बीजापुर को प्रवासित परिवारों के सर्वे किया जाकर 15 दिन के भीतर प्रतिवेदन प्रेषित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि सर्वे अनुसार जिला दंतेवाड़ा से तेलंगाना प्रदेश के 60 ग्राम में 618 परिवार के 2654 व्यक्ति एवं जिला सुकमा से तेलंगाना प्रदेश के 293 ग्राम में 2733 परिवार के 12026 व्यक्ति तथा जिला बीजापुर से तेलंगाना प्रदेश के 114

ग्राम में 994 परिवार के 5029 व्यक्ति प्रवासित है। इस तरह छत्तीसगढ़ राज्य के उक्त तीनों जिला से तेलंगाना राज्य के 467 ग्राम में 4345 परिवार के 19709 व्यक्ति प्रवासित है।

इसी तरह जिला दंतेवाड़ा से आंध्रप्रदेश के 25 ग्राम में 125 परिवार के 568 व्यक्ति एवं जिला सुकमा से आंध्रप्रदेश के 155 ग्राम में 2462 परिवार के 10787 व्यक्ति तथा जिला बीजापुर से आंध्रप्रदेश के 04 ग्राम में 07 परिवार के 34 व्यक्ति प्रवासित है। इस तरह से छत्तीसगढ़ राज्य के उक्त तीनों जिला

से आंध्रप्रदेश राज्य के 184 ग्राम में 2594 परिवार के 11389 व्यक्ति प्रवासित है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य के जिला दंतेवाड़ा, सुकमा एवं बीजापुर के 667 ग्राम से तेलंगाना एवं आंध्रप्रदेश राज्य के 651 ग्राम में 6939 परिवार के 31098 व्यक्ति प्रवासित है। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री पिंगुआ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बस्तर संभाग श्री डोमन सिंह एवं पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रंज श्री सुन्दरराज से चर्चा कर अन्य प्रांतों में प्रवासित परिवारों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए एक बार और सीमावर्ती राज्यों के अधिकारियों से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर लें।

इसी तरह से श्री पिंगुआ ने कलेक्टर दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा से कहा है कि वे अपने-अपने जिलों से अन्य प्रांतों में प्रवासित लोगों के बारे में उनके मूल ग्राम एवं निवास स्थान से आवश्यक जानकारी तैयार कर लें। जिससे पुनर्वास योजना बनाने आसानी होगी। इसी तरह से पुनर्वास योजना

बनाने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देशित दिए गए है कि वे शीघ्र ही अपने-अपने विभागों के नोडल अधिकारी नियुक्त कर दें, जिससे शीघ्र पुनर्वास योजना बनाने में आसानी होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती त्र्छाा शर्मा, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगम, गृह विभाग की सचिव श्रीमती नेहा चम्पावत, आईजी बस्तर श्री सुन्दरराज, कमिश्नर बस्तर श्री डोमन सिंह सहित कलेक्टर दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा शामिल हुए। इसी तरह से बैठक में सामान्य प्रशासन, वित्त विभाग, राजस्व, स्कूल शिक्षा, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, वाणिज्य एवं उद्योग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी शामिल हुए।

दुनिया को चीन की ऊर्जा नीति से सीख लेनी चाहिए

नीरज कुमार दुबे

वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच एक सख्त सच्चाई उभर कर सामने आ रही है। होर्मुज जलडमरूमध्य पर मंडराते खतरे ने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी हैं, लेकिन इस उथल पुथल के बीच चीन एक अलग ही खेल खेलता नजर आ रहा है। जहां एशिया के कई देश ऊर्जा बचाने की अपील कर रहे हैं, वहीं चीन आत्मविश्वास से भरा हुआ है और दावा कर रहा है कि उसके पास ऊर्जा का पर्याप्त रणनीतिक भंडार है। दरअसल, यह आत्मविश्वास यूं ही नहीं आया। चीन ने पिछले कई वर्षों में एक ऐसी रणनीति तैयार की है जिसने उसे वैश्विक तेल आपूर्ति के झटकों से काफी हद तक सुरक्षित बना दिया है। जब दुनिया तेल के लिए समुद्री मार्गों पर निर्भर है, चीन ने अपनी निर्भरता को योजनाबद्ध तरीके से कम किया है। सबसे बड़ा बदलाव चीन के इलेक्ट्रिक वाहन अभियान में दिखता है। जहां 2020 में लक्ष्य रखा गया था कि 2025 तक नए वाहनों में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक वाहनों की होगी, वहीं यह आंकड़ा अपेक्षा से कहीं आगे निकल गया और आधे से ज्यादा नई गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो गई। इसका सीधा असर यह हुआ कि चीन की तेल खपत अब स्थिर होने लगी है। आंकड़े बताते हैं कि केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के कारण जितना तेल बचा है, वह लगभग उतना ही है जितना चीन सऊदी अरब से आयात करता था। यह बदलाव मामूली नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा भू राजनीति की दिशा बदलने वाला संकेत है। चीन की दूसरी सबसे बड़ी ताकत उसका विविधीकृत आयात तंत्र है। जहां जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश एक या दो आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर हैं, वहीं चीन ने अपने तेज स्रोतों को आठ से ज्यादा देशों में फैला रखा है। रूस, ईरान, वेनेजुएला जैसे देशों से सस्ता तेल लेकर उसने पश्चिमी प्रतिबंधों को भी अपने हित में बदल लिया है। रणनीतिक दृष्टि से यह कदम बेहद महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि यदि किसी एक क्षेत्र में संकट आता है, तो चीन पूरी तरह ठप नहीं होगा। तीसरा और सबसे खतरनाक दांव है चीन का विशाल तेल भंडार। अनुमान है कि उसके पास इतना तेल जमा है कि वह होर्मुज मार्ग बंद होने की स्थिति में करीब सात महीने तक अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। यह भंडारण केवल आर्थिक सुरक्षा नहीं बल्कि सामरिक हथियार भी है। देखा जाये तो ऊर्जा सुरक्षा के इस खेल में चीन ने केवल तेल पर ही भरोसा नहीं किया है। उसकी बिजली व्यवस्था लगभग आत्मनिर्भर हो चुकी है। कोयले और तेजी से बढ़ती नवीकरणीय ऊर्जा के दम पर चीन ने अपने ग्रिड को बाहरी निर्भरता से लगभग मुक्त कर लिया है। इसके साथ ही सौर और पवन ऊर्जा का विस्फोटक विस्तार इस बात का संकेत है कि चीन भविष्य की ऊर्जा लड़ाई के लिए पहले ही तैयार है। इसका सीधा असर यह हुआ है कि उसे कम एलएनजी आयात करना पड़ रहा है और तटीय इलाकों की निर्भरता भी घट रही है। गैस के मामले में भी चीन ने चालाकी दिखाई है। पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए उसने रूस, मध्य एशिया और म्यांमार से सीधी आपूर्ति सुनिश्चित कर ली है। इससे समुद्री मार्गों पर निर्भरता और कम हो गई है। सामरिक नजरिए से देखें तो यह पूरी रणनीति एक गहरी सोच का परिणाम है। चीन ने समझ लिया था कि भविष्य की जंग केवल हथियारों से नहीं बल्कि ऊर्जा पर नियंत्रण से जीती जाएगी। बहरहाल, यह पूरा घटनाक्रम एक साफ संदेश देता है। जो देश समय रहते अपनी ऊर्जा रणनीति नहीं बदलेंगे, वे आने वाले संकटों में बुरी तरह फंस सकते हैं। चीन ने यह साबित कर दिया है कि दीर्घकालिक योजना, आक्रामक निवेश और रणनीतिक विविधीकरण के दम पर किसी भी वैश्विक संकट को मात दी जा सकती है। अब सवाल यह है कि क्या बाकी दुनिया इस सबक को समझेगी या फिर संकट उन्हें पूरी तरह झकझोर देगा।

पुराण दिग्दर्शन

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे....)

तदनुसार घर्म-शास्त्र सम्बन्धी परस्त्रीगमन रूप निषेध स्थूलशरीरधारी मनुष्य जाति तक ही सीमित रहेगा। भोगयोनित होने की हैसियत से सुक्ष्मशरीर-धारी इन्द्रादि देव इन नियमों में आबद्ध नहीं हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त इन्द्र ने केवल कामवासना की पूर्ति के लिये यह अकार्य नहीं किया है बल्कि गोत्तम की उग्र तपश्चर्या से समस्त देव भयभीत थे, यह खड़तल मषि अपने उग्र स्वभाव के कारण प्रख्यात हो चुका था। उस दिन जन्मस्थान के रहने वाले अतिथिभूत कुछ एक मुनियों से बिराड़ कर आपन हरे भरे दण्डकारण्य नामक वन को अनावृष्टि का शाप देकर उजाड़ बना दिया था, यह परम प्रसिद्ध कथा प्रत्येक रमायणपाठी को प्रायः विदित है, अतः यहाँ विस्तार करने की आवश्यकता नहीं। सो जब समस्त देवताओं ने गोत्तम जी को घोर तपश्चर्या करते देखा तो सहसा उन्हें खयाल हुआ कि –



विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय – के अनुसार कदाचित् अब भी गोत्तम जी इस तपोबल के दुरुपयोग से संसार में कोई न कोई नया अप्रिय काण्ड खड़ा करेंगे! अतः समस्त सप्सार के कल्याण के लिए समय से पूर्व ही किसी भीति इनके तपोबल का अपव्यय करा देना चाहिए, जिससे न होगा बाँस न बजेगी बाँसुरी-वाली कहावत के अनुसार तपोबल के न रहने से यह किसी का कुछ भी न बिगाड़ सकेंगे ? देवसमाज का यह विचार गोत्तम जी के लिये अच्छा न हो परन्तु दण्डक जैसे लहलहीलतिकाभिलक्षित, शश्य-श्यामल प्रदेश को आन की आन में वियाबान बना देने वाले अवखड़ व्यक्तिके हाथ में तपोबलगण दुधारा खड्ग आता देखकर किस सर्व-हित-चिन्तक महानुभावके हृदय में भावी अनर्थ की सम्भावना से व्य्था न होगी यह भी तो एक विचारणीय समस्या है।
क्रमशः ...

वैश्विक संकट : मानवता की अंतिम सुरक्षा-रेखा है ऊर्जा संरक्षण

योगेश कुमार गोयल

आज जब विश्व एक बार फिर भू-राजनीतिक तनावों के दौर से गुजर रहा है और ईरान, अमेरिका तथा इजरायल के बीच टकराव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को अस्थिर कर दिया है, तब ऊर्जा केवल विकास का साधन नहीं बल्कि अस्तित्व का प्रश्न बन चुकी है। तेल और गैस के दामों में उतार-चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान और ऊर्जा स्रोतों पर बढ़ती निर्भरता ने पूरी दुनिया को यह सोचने पर विवश कर दिया है कि क्या आधुनिक सभ्यता ने अपनी बुनियाद अत्यधिक अस्थिर संसाधनों पर खड़ी कर दी है। इस परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण केवल एक विकल्प नहीं बल्कि मानवता की सुरक्षा का सबसे सरल, सस्ता और प्रभावी उपाय बनकर उभर रहा है। ऊर्जा आधुनिक जीवन का अभिन्न अंग है, चाहे वह उद्योगों की मशीनें हों, परिवहन के साधन हों, डिजिटल अर्थव्यवस्था हो या घरेलू जीवन की सुविधाएं किंतु विडंबना यह है कि जिस ऊर्जा पर हमारी प्रगति आधारित है, वही अब संकट का कारण बनती जा रही है।

संयुक्त राष्ट्र की ‘एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024’ के अनुसार आने वाले दशक में वैश्विक ऊर्जा मांग में लगभग 25 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है जबकि जीवाश्म ईंधनों के भंडार तेजी से सीमित होते जा रहे हैं। ऐसे में यदि ऊर्जा संरक्षण और दक्षता को प्राथमिकता नहीं दी गई तो भविष्य में ऊर्जा संकट केवल आर्थिक चुनौती नहीं रहेगा बल्कि सामाजिक अस्थिरता और वैश्विक संघर्षों का कारण भी बन सकता है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य इस खतरे को और स्पष्ट करता है। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव ने तेल आपूर्ति पर अनिश्चितता बढ़ा दी है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अस्थिर हो रही हैं। भारत जैसे ऊर्जा आयात पर निर्भर देशों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। दरअसल भारत अपनी कुल तेल आवश्यकता का लगभग 85 प्रतिशत आयात करता है। ऐसे में वैश्विक संकट का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था, महंगाई



और आम नागरिक के जीवन पर पड़ता है। पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि केवल परिवहन लागत को नहीं बढ़ाती बल्कि खाद्य पदार्थों से लेकर निर्माण सामग्री तक हर क्षेत्र में महंगाई को जन्म देती है। इस परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा का भी एक महत्वपूर्ण आधार बन जाता है।

भारत तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है और यहां ऊर्जा की मांग निरंतर बढ़ रही है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की ‘इंडिया एनर्जी आउटलुक 2024’ रिपोर्ट के अनुसार, 2030 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी ऊर्जा उपभोक्ता अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ऐसे में यदि ऊर्जा खपत को संतुलित नहीं किया गया तो विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाएगा। यही कारण है कि भारत ने ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को अपनी नीति का केंद्रीय तत्व बनाया है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा लागू ऊर्जा संरक्षण अधिनियम और ‘उजाला’ जैसे कार्यक्रमों ने यह साबित किया है कि छोटे-छोटे प्रयास भी बड़े परिणाम दे सकते हैं। 36 करोड़ से अधिक एलईडी बल्बों का वितरण और उससे हुई 48 बिलियन यूनिट बिजली की बचत इस बात का प्रमाण है कि यदि नीति और जनभागीदारी साथ आएंगे तो ऊर्जा संरक्षण एक जनांदोलन बन सकता है।

ऊर्जा संरक्षण का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह किसी नई तकनीक या बड़े निवेश पर निर्भर नहीं है बल्कि यह हमारे दैनिक व्यवहार में छोटे-छोटे बदलावों से ही संभव है। उदाहरण के लिए, अनावश्यक रूप से जलती लाइटों को बंद करना,

ज्ञान/मीमांसा

संकल्प के साथ राष्ट्रीय समस्या नक्सलवाद का अंत

प्रमोद भार्गव

भारत में संकट बन चुकी राष्ट्रीय समस्याओं का समय-सीमा में अंत होना दुर्लभ है, लेकिन केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने यह कार्य करके दिखा दिया। गुहमंत्री अमित शाह लगातार कहते रहे हैं कि माओवादी नक्सलवाद का अंत 31 मार्च 2026 तक कर लिया जाएगा। उन्होंने यह करके दिखा भी दिया। वरना नक्सलवाद को संरक्षण दे रहे नगरीय तथाकथित बौद्धिक इस सशस्त्र खुनी क्रांति को राष्ट्र विरोधी संघर्ष मानते ही नहीं थे। बस्तर में 25 लाख के इनामी नक्सली सरगना पापा राव ने अपने 17 साथियों के साथ जिस तरह से हथियारों सहित समर्पण किया, उससे देश के सबसे बड़े गढ़ में माओवादी हिंसा का निर्णायक अंत हो गया। क्योंकि इस क्षेत्र का यही अंतिम सरगना शेष बचा था। नक्सलवाद का अंत ठीक उसी तरह हुआ है, जिस तरह प्रधामंत्री पीवी नरसिंह राव के कार्यकाल में पंजाब के उग्रवाद का अंत हुआ था। इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुहमंत्री अमित शाह की दृढ़ इच्छा शक्ति को जाता है। अब पूरा देश मान रहा है कि भारत में राजनीतिक नेतृत्व दृढ़ हो तो किसी भी समस्या का निपटारा किया जा सकता है। क्योंकि देश की जिस तरह की सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियां हैं और सफ़्त प्रशासनिक ढांचा है, उसके चलते किसी भी प्रकार की सशस्त्र क्रांति का उग्रवाद और नक्सलवाद की तरह अंत होना निश्चित है। कश्मीर का पाक प्रायोजित आतंकवाद का भी यही हथ्र होना है।

छत्तीसगढ़ और आंध्रप्रदेश की सीमा पर हुई मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने शीर्ष माओवादी वरुर् हिसा के प्रतीक बन चुके हिड़मा को मार गिराने के पहले छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के जंगल में सुरक्षा बलों के नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता तब मिली थी, जब डेढ़ करोड़ के इनामी बसव राजू समेत 27 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। यह कुख्यात दरिदा होने के साथ गुरिल्ला लड़ाका था। माओवादी पार्टी का इसे पर्याय माना जाता था। इसका नक्सली सफर 1985 से शुरू हुआ था। इसने वारांगल के क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई की थी।

नक्सली हिंसा लंबे समय से देश के अनेक प्रांतों में आंतरिक मुसीबत बनी हुई है। वामपंथी माओवादी उग्रवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के



योगेश कुमार गोयल

यीशु (ईसा मसीह) के बलिदान और उनकी शिक्षाओं को याद करने का दिन है ‘गुड फ्राइडे’। दरअसल ईसा मसीह ने मानवता की भलाई के लिए बलिदान दिया। ईसाई मान्यता के अनुसार दुनिया को प्रेम, दया, करुणा, परोपकार, अहिंसा, सद्ब्यवहार और पवित्र आचरण का संदेश देने वाले यीशु को इसी दिन उस जमाने के धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा क्रॉस पर चढ़ाया गया था। जिस दिन ईसा मसीह ने प्राण त्यागे थे, उस दिन शुक्रवार था और इसी के रविवार से पहले पड़ने वाले शुक्रवार को मनाया जाता है और इस वर्ष गुड फ्राइडे 3 अप्रैल को मनाया जा रहा है। ईसाई समुदाय द्वारा इस त्यौहार को शोक के रूप में मनाया जाता है। गुड फ्राइडे को यीशु

ऊर्जा-कुशल उपकरणों का उपयोग करना, एयर कंडीशनर का सीमित प्रयोग, सार्वजनिक परिवहन को अपनाना और सौर ऊर्जा जैसे विकल्पों को बढ़ावा देना, ये सभी कदम न केवल ऊर्जा बचाते हैं बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखते हैं। यदि भारत का प्रत्येक परिवार प्रतिदिन केवल एक यूनिट बिजली की बचत करे तो यह देश के लिए ऊर्जा क्रांति के समान होगा। ऊर्जा संरक्षण का संबंध केवल बिजली तक सीमित नहीं है बल्कि यह जल, पर्यावरण और स्वास्थ्य से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। ऊर्जा उत्पादन में जल का व्यापक उपयोग होता है और जल की बर्बादी सीधे ऊर्जा की बर्बादी में बदल जाती है। इसी प्रकार, ऊर्जा के अत्यधिक उपयोग से कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है, जो जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान वृद्धि का मुख्य कारण है। आज जब दुनिया 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, तब ऊर्जा संरक्षण इस दिशा में सबसे प्रभावी हथियार साबित हो सकता है।

अक्षय ऊर्जा इस संकट का दीर्घकालिक समाधान प्रस्तुत करती है लेकिन इसकी सफलता भी ऊर्जा संरक्षण पर ही निर्भर करती है। सौर, पवन और जैव ऊर्जा जैसे स्रोतों का विस्तार तभी प्रभावी होगा, जब ऊर्जा की कुल मांग को नियंत्रित किया जाए। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है बल्कि वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और स्मार्ट ग्रिड जैसी तकनीकें इस दिशा में नई संभावनाएं खोल रही हैं लेकिन इन सबका मूल आधार ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग ही है। शहरीकरण के बढ़ते दबाव ने भी ऊर्जा खपत को तेजी से बढ़ाया है। महानगरों में ऊंची इमारतें, एयर कंडीशनिंग सिस्टम और बढ़ती वाहन संख्या ऊर्जा की मांग को कई गुना बढ़ा देती है। ऐसे में हरित भवन निर्माण, सौर पैनलों का उपयोग और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना



इसमें कोई दो राय नहीं कि छत्तीसगढ़ में नक्सली तंत्र को कमजोर करने की दृष्टि से सरकार ने बहुआयामी कदम उठाए। सबसे पहले उन नगरीय बौद्धिकों पर शिकंजा कसा, जो इन्हें राष्ट्रविरोधी वामपंथी वैचारिक खुराक देते थे। केंद्र सरकार ने सुरक्षाबलों को आधुनिक हथियार एवं यांत्रिक सुविधाएं देकर इन्हें सशक्त बनाया।

लिए बड़ा खतरा माना जाता रहा है। लेकिन चाहे जहां रक्तपात की नदियां बहाने वाले इस उग्रवाद पर लगभग नियंत्रण किया जा चुका है। इसलिए अमित शाह ने लोकसभा में ‘नक्सल मुक्त भारत’ मुद्दे पर चली चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि ‘एक समय 12 राज्य लाल आतंक का गलियारा बन गए थे। कानून व्यवस्था नहीं थी। देश में अब नक्सलवाद खत्म हो गया है। शाह ने बताया कि इस दौरान 706 नक्सली मारे गए, 4800 ने समर्पण किया हैं और 2000 गिरफ्तार हुए हैं। इस समस्या के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस को घेरते हुए शाह ने कहा, ‘75 साल में 60 साल कांग्रेस ने राज किया। लेकिन उसने आदिवासियों को न घर दिए, न पानी न स्कूल बनाए और न ही बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाई 1% शाह का यह बयान तर्कसंगत है, क्योंकि शहरी वामपंथियों से भयभीत कांग्रेस नेतृत्व नक्सलवाद को कश्मीर के आतंकवाद और पूर्वोत्तर के उग्रवाद की तरह बड़ी चुनौती तो मानती थी, लेकिन उससे निपटने की कभी कोई कठोर रणनीति नहीं बनाई। यही कारण रहा कि छत्तीसगढ़ के जगदलपुर इलाके में नक्सली आतंक बेखौफ फलात-फूलता रहा।

इसमें कोई दो राय नहीं कि छत्तीसगढ़ में नक्सली तंत्र को कमजोर करने की दृष्टि से सरकार ने बहुआयामी कदम उठाए। सबसे पहले उन नगरीय बौद्धिकों पर शिकंजा कसा, जो इन्हें

गुड फ्राइडे



द्वारा मानवता की भलाई के लिए दिए बलिदान के रूप में देखा जाता है। गुड फ्राइडे के दिन गिरजाघरों में घंटा नहीं बजाया जाता बल्कि लकड़ी के खटखटे बजाए जाते हैं और लोग चर्च में क्रॉस को चूमकर यीशु का स्मरण करते हैं। कुछ स्थानों पर लोग काले कपड़े पहनकर प्रभु यीशु के बलिदान दिवस पर शोक भी व्यक्त करते हैं और यीशु से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाए जाने की याद में इस दिन उनके अनुयायी समस्त जातों के रविवार से पहले पड़ने वाले शुक्रवार को मनाया जाता है और इस वर्ष गुड फ्राइडे 3 अप्रैल को मनाया जा रहा है। ईसाई समुदाय द्वारा इस त्यौहार को शोक के रूप में मनाया जाता है। गुड फ्राइडे को यीशु

कैथोलिकों द्वारा शुरू की गई प्रथा के अनुसार गुड फ्राइडे के ठीक 40 दिन पहले

आने वाले बुधवार से ईसाई समुदाय में प्रार्थना और उपवास प्रारंभ हो जाते हैं। इस बुधवार को ‘राख का बुधवार’ कहा जाता है। उपवास के दौरान लोग केवल शाकाहारी और सात्विक भोजन करते हैं। माना जाता है कि यीशु ने मानव सेवा

प्रारंभ करने से पहले चालीस दिन तक व्रत किया था और संभवतः इसीलिए उपवास की यह परम्परा शुरू हुई। इस दिन दुनियाभर के ईसाई सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए चर्च में चंदा या दान देते हैं। ईसाई धर्म में ईसा मसीह को परमेश्वर का पुत्र माना जाता है। उन्होंने लोगों को क्षमा, शांति, दया, करुणा, परोपकार, अहिंसा, सद्ब्यवहार और पवित्र आचरण का उपदेश दिया और उनके इन्हीं सदगुणों के कारण लोग उन्हें शांति दूत, क्षमा

मूर्ति और महात्मा कहकर पुकारने लगे थे। कहा जाता है कि वे यरूशलम के गैलिली प्रांत में लोगों को मानवता, सत्य, एकता, प्रेम, अहिंसा और शांति का उपदेश फैलाने करते थे। उनके संदेश दूर-दूर तक फैलने लगे और उनके विचारों को लोग अपने जीवन में अपनाने लगे। वहां के लोग उन्हें परमपिता परमेश्वर का दर्जा देने लगे थे। समाज में धार्मिक अंधविश्वास और झूठ फैलाने वाले धर्मगुरुओं को इसी कारण ईसा मसीह से काफी जलन होने लगी थी क्योंकि लोग अपनी समस्याओं को लेकर अब उनके पास नहीं आ रहे थे। करीब दो हजार वर्ष पूर्व उन्हें मृत्युदंड इसीलिए दिया गया क्योंकि वे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और घोर विलासिता तथा अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के लिए लोगों को शिक्षित और जागरूक कर रहे थे।

आज का इतिहास

- 1933 विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के ऊपर से पहली बार विमान ने उड़ान भरी।
- 1936 रिचर्ड हाउटनमैन को लिंबुर्ग बेबी की हत्या और हत्या के लिए इलेक्ट्रिक चेयर में मार दिया गया था।
- 1942 जर्मन पनडुब्बी –702 उत्तर समुद्र के खदान में खो गयी।
- 1946 इम्पीरियल जापानी सेना के अधिकारी मासाहारु होमा को बाटन ड्यू मार्च से संबंधित युद्ध अपराधों के लिए मार डाला गया था।
- 1948 जीजू द्वीप पर एक विद्रोह शुरू हुआ, अंततः विभिन्न गुटों के बीच लड़ाई के कारण 14,000 और 30,000 व्यक्तियों के बीच संघर्ष हुआ और दक्षिण कोरियाई सेना ने विद्रोह का हिंसक दमन किया।
- 1948 मार्शल प्लान, एक आर्थिक सुधार कार्यक्रम है जिसे यूरोप के बाद के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के निर्माण में सहायता के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल द्वारा स्थापित किया गया था।
- 1949 अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर किए।
- 1961 50 वर्ष से अधिक समय से विलुप्त हो रहे एक व्यक्तिगत लीडब्रीटर के कब्जे की खोज न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में की गई थी।
- 1968 अमेरिकन फिल्म प्लैनेट ऑफ द प्रंस थिएटरों में रिलीज हुई।
- 1971 जापानी टोकनससु टेलीविजन श्रृंखला कामेन राइडर का प्रीमियर हुआ, जो लंबे समय से चल रहे कामेन राइडर मताधिकार की शुरुआत थी।
- 1973 न्यूयॉर्क शहर की एक सड़क पर, मोटोरोला के शोधकर्ता मार्टिन कोपरमेड ने एक हाथ में मोबाइल फोन पर पहली सार्वजनिक कॉल की।
- 1981 ओसबोर्न 1 , पहला सफल पोर्टेबल कंप्यूटर, सैनफ्रांसिस्को के वेस्ट कोस्ट कंप्यूटर फेयर में अनावरण किया गया था।
- 1987 अटलांटिक सिटी के न्यू जर्सी में शोबोट कैसीनो होटल की स्थापना की गयी।
- 1981 ओसबोर्न 1 , पहला सफल पोर्टेबल कंप्यूटर, सैनफ्रांसिस्को के वेस्ट कोस्ट कंप्यूटर फेयर में अनावरण किया गया था।
- 1987 अटलांटिक सिटी के न्यू जर्सी में शोबोट कैसीनो होटल की स्थापना की गयी।
- 2010 चीन के शांक्सी में बचाव दल ने 153 से अधिक श्रमिकों की मदद के लिए बाढ़ की खान में प्रवेश किया।
- 2011 कजाखस्तान में राष्ट्रपति चुनाव; राष्ट्रपति नूरसुल्तान नज़रबायेव ने 95% वोट जीते।
- 2012 रूस की राजधानी मास्को में भीषण आग में 17 प्रवासी श्रमिकों की मौत।
- 2013 अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स प्रांत के उत्तरपूर्वी हिस्से में कई फ्लैश बाढ़ का अनुभव हुआ, जिसने कम से कम 100 लोगों के जीवन का दावा किया।

देश यूं ही नहीं हुआ नवसलवाद से मुक्त

अवधेश कुमार

गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में घोषणा की कि लाल आतंक की परछाईं हट गई है। यह ऐसी घोषणा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। जब गृह मंत्री ने पिछले वर्ष घोषित किया था कि 31 मार्च, 2026 तक देश नक्सली आतंक से मुक्त हो जाएगा तो एक्विविस्टों, पत्रकारों, नेताओं, एन.जी.ओ. चलाने वाले, बुद्धिजीवियों आदि की बड़ी फौज ने अलग-अलग तरीकों से उनका निशाना बनाना, उपहास उड़ाना और प्रचंड तरीके से विरोध आरंभ कर दिया था।

गृह मंत्री ने घोषणा की कि 2024 तक नक्सलियों की शीर्ष केंद्रीय कमेटी और पुलिस ब्यूरो में 21 मुख्य कैंडर थे जो पूरे नेटवर्क को चलाते थे। इनमें से एक पकड़ा गया, 7 ने आत्मसमर्पण किया और 12 मारे गए तथा एक फरार है। उसके साथ भी आत्मसमर्पण के लिए बातचीत चल रही है। वस्तुतः वह मिसिर बेसरा है जो झारखंड के सारंडा जंगलों में अपने 50 साथियों के साथ छिपा है। वह आत्मसमर्पण करता है या मारा जाता है, तो हथियारों के बल पर संघर्ष करने वालों की

सूची समाप्त हो जाएगी। जरा सोचिए, 2014 में जो नक्सल प्रभावित जिले 126 थे, वे अब घटकर मात्र 2 रह गए हैं। वे भी केवल नाम मात्र के। रैड कॉरिडोर या लाल गलियारा के नाम से पहचाने जाने वाले पूरे क्षेत्र में 12 राज्य और 70 प्रतिशत भूभाग शामिल था। आप यू.पी.ए. शासनकाल को याद करिए, जब भी आंतरिक सुरक्षा का सम्मेलन होता था, राज्यों के पुलिस प्रमुखों, गृह सचिवों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के भाषण में यह पंक्ति रहती ही थी कि आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा माओवाद है।

पिछले लगभग 12 वर्ष की नक्सलवाद या माओवाद विरुद्ध मोदी सरकार की नीति का मूल्यांकन करेंगे तो एक निष्कर्ष यह आएगा कि राजनीतिक नेतृत्व के अंदर समस्याओं को लेकर संवेदनशीलता व सही समझ हो, उसके अंत करने के उपाय के प्रति दृष्टि साफ और संकल्पबद्धता हो तो परिणाम ऐसा आ सकता है। इस सुखद स्थिति के पीछे कई स्तरीय रणनीति थी। सख्त सुरक्षा कार्रवाई, माओवादियों से संपर्क कर उन्हें आत्मसमर्पण और सामान्य जीवन में आने के लिए प्रेरित



करने का सतत अभियान, उनका आर्थिक ढांचा तोड़ना, क्षेत्र की विकास गतिविधियों के साथ स्थानीय लोगों से संपर्क एवं उनके अंदर सुरक्षा मिलने का आश्वासन पैदा करना।

सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवाद बन चुके बड़े नक्सली नामों को संघर्ष में समाप्त किया। सुरक्षा कार्रवाइयों के दबाव में हजारों का आत्मसमर्पण हुआ। आर्थिक कमर तोड़ने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन.आई.ए.) और प्रवर्तन निदेशालय को दायित्व दिया गया, जिससे नक्सलियों से अवैध करोड़ों रुपए जब्त किए गए। धन शोधन निवारण अधिनियम (पी.एम.एल.ए.) के तहत मामले दर्ज हुए और नक्सलियों को धन देने वालों को गिरफ्तार किया गया। इसके समानांतर नक्सल

प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए बजट आबंटन में 300 प्रतिशत की वृद्धि की गई। प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क लगे, सड़कें बनीं, राशन की दुकानें खुलीं, स्कूल चलाने की कोशिश हुई, स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई गईं, बैंक, ए.टी.एम. और डाकघर खोले गए। रोजगार प्रशिक्षण के लिए आई.टी.आई. और कौशल केंद्र बनाए गए। सुरक्षा बलों के साए में सांस्कृतिक-धार्मिक-सामाजिक गतिविधियों में लोगों को शामिल करने की कोशिश हुई और उनके अंदर का भय मिटता गया तथा उनका भी सहयोग मिलने लगा। आत्मसमर्पण नीति लागू की गई, जिसमें आत्मसमर्पण करने वालों को आर्थिक मदद और पुनर्वास दिया गया। सरकार ने हर गांव तक पहुंच बनाई।

क्रूरता, निर्दयता और दमन करने के आरोप लगाने वालों के सामने गृह मंत्री ने लोकसभा में आंकड़ा देते हुए कहा कि सन् 2024 से अब तक 706 नक्सली मारे गए जबकि उनकी तुलना में 2218 गिरफ्तार किए गए तथा 4849 ने आत्मसमर्पण किया। बात सीधी है और जैसा गृह मंत्री ने कहा कि मैं 50 बार कह चुका हूँ कि हथियार डाल दो सरकार

पुनर्वास की व्यवस्था करेगी। हथियार नहीं डाले तो जो गोली चलाएगा उसका जवाब गोली से मिलेगा यही सरकार की नीति है। ईमानदारी से विश्लेषण करेंगे तो निष्कर्ष यही आएगा कि गरीबों के कारण नक्सलवाद या माओवाद नहीं बढ़ा बल्कि लोगों को भड़का कर बरगला कर हथियार थमाए गए। उन्होंने अस्पताल, स्कूल जला दिए, सड़कें तोड़ दीं, खदान बंद कराए, जंगलों में मछली पालन से लेकर अन्य काम बंद हो गए, लोगों का बाहर जाना बंद कर दिया तो उनके सामने गरीबी और तंगहाली में आंसू बहाकर जीने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। करीब 30 हजार लोगों की जान चली गई, जिनमें 5000 सुरक्षा कर्मी भी शामिल थे।

1967 में बंगाल के नक्सलबाड़ी से आरंभ आंदोलन आखिर इतना भयानक कैसे हो गया कि सरकार की पहुंच उन क्षेत्रों में समाप्त हो गई? सरकार की नीतियां सही होतीं तो तिरुपति से पशुपतिनाथ तक इतना बड़ा रैड कॉरिडोर कैसे बन सकता था? अगर सत्ता का समर्थन था ही नहीं तो 5 जुलाई, 2011 को नंदिनी सुंदर और अन्य लोगों द्वारा दायर एक

याचिका के बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति सुरेश्रन रेड्डी की अध्यक्षता वाली पीठ ने सलवा जुद्ध के बारे में फैसला देते हुए कहा कि माओवादियों के विरुद्ध लड़ाई गैर कानूनी थी। परिणाम यह निकला कि माओवादियों ने सलवा जुद्ध से जुड़े लोगों की हत्या कर दी और कांग्रेस ने सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया। इसका मतलब क्या हुआ? यह बात तो सत्य है कि राहुल गांधी ने 2018 में हैदराबाद में माओवादी घुमांडी विद्रुल राव से मुलाकात की। 2025 में कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पीस के साथ मुलाकात की। हिडमा जब मारा गया, तब इंडिया गेट पर ‘कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा’ के नारे लगे जिसका वीडियो राहुल गांधी ने पोस्ट किया। बहरहाल, गृह मंत्री की इस घोषणा को आश्वासन माना जाना चाहिए कि सरकार मुद्दों के प्रति संवेदनशील है, वह सभी शिकायतें सुनने के लिए तैयार और हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। किंतु देश में माओवादी ड़्क़हसा करने वालों के दिन अब खत्म हो गए हैं, हथियार उठाने वालों को हिसाब देना होगा।

दीर्घकालिक असर डालते हैं युद्धों से होने वाले परोक्ष नुकसान

डॉ. रहीस सिंह

आज की दुनिया को देखकर न जाने क्यों यह लगने लगता है कि एक दुनिया मर रही है और जो कुछ भी नया जन्म ले रहा है, वह दुनिया के लिए अपेक्षित तो नहीं है। मैं बात उन युद्धों की कर रहा हूँ जो दुनिया को धीरे-धीरे करके मार रहे हैं और किसलिए? सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं और अहमन्यताओं के लिए? ये युद्ध भले ही रूस-यूक्रेन या फिर ईरान-अमेरिका और इजराइल के बीच दिख रहे हों लेकिन इनसे पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। दुनिया इसे भले ही माँसको, कीव, तेहरान, तेल अवीव और वाशिंगटन के सहारे देख रही हो लेकिन सच यह है कि पूरी दुनिया इनमें सिमटी और लिपटी हुई है। अगर ये युद्ध न रुके तो परिणाम बेहद गंभीर और मानवता के लिए अत्यंत हानिकारक होंगे, इतने कि जितना अनुमान भी न किया जा सके। कोई भी युद्ध अब युद्ध के मैदान में नहीं लड़ा जाता, बल्कि वह शहरों से कस्बों और कस्बों से जंदिगियों के बीच भी लड़ा जाता है। उसमें क्षति केवल संसाधनों की नहीं होती बल्कि जंदिगियों की भी होती है, हां अंतर इतना है कि संसाधनों में हुई क्षति कैलकुलेटिव होती है लेकिन जंदिगियों की क्षति? युद्ध और युद्धोत्तर काल में लाखों-लाख लोग इसके प्रभाव का सामना करते हैं फिर वे विस्थापन का शिकार होकर करें अथवा भूख का। रूस और यूक्रेन युद्ध से प्रभावित दुनिया अब ईरान केंद्रित अमेरिका और इजराइल युद्ध का सामना कर रही है जिसे लेकर अर्थव्यवस्था और लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव की चिंताएं हर तरफ दिखने लगी हैं। ऊपरी तौर पर तो इस प्रभाव को तेल और गैस संकट तक सीमित कर देखा जा रहा है लेकिन युद्ध का प्रभाव कभी रेखीय (लीनियर) नहीं होता, बल्कि घातीय (एक्सपोजेंशियल) होता है। गौर

से देखें तो मध्य-पूर्व के संघर्ष ने एशियाई व घरेलू शेयर बाजारों में निराशा का भाव पैदा कर दिया है। इसकी एक वजह तो होर्मुज जलडमरूमध्य में भारी गतिरोध है जिसके कारण वैश्विक ऊर्जा संकट बढ़ा है और फारस की खाड़ी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई चेन टूटने की ओर बढ़ती दिख रही है। वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 100 डॉलर से ऊपर पहुंच चुकी हैं और ऐसी शंका जताई जा रही है कि यदि युद्ध तत्काल नहीं रुका तो ये कीमतें 150 डॉलर तक पहुंच सकती हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद 2022 में क्रूड ऑयल की कीमत आखिरी बार तीन अंकों में पहुंची थी। ऊपरी तौर पर तो इस प्रभाव को तेल और गैस संकट तक सीमित कर देखा जा रहा है लेकिन यह खाद (फर्टिलाइजर) और खाद्यान्न तक जाएगा जिससे न केवल उत्पादन की लागतें बढ़ेंगी बल्कि जंदिगियों को जीने का खर्च भी बढ़ जाएगा। ईरान युद्ध की वजह से होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) से गायब होते तेल और एलएनजी टैंकरों पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। कारण यह कि ईरान और ओमान के बीच मौजूद इस संकरे समुद्री मार्ग से होकर दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत कच्चा तेल और एलएनजी गुजरती है। अब इस ऊर्जा संकट के साथ-साथ युद्ध के आईने से उन जहाजों पर नजर भी गड़ाए जिनमें खेती के लिए खाद और लोगों के लिए भोजन लदा हुआ होता है। यदि यह रास्ता बंद कर दिया जाए तो? जैसा कि अभी है। तो उन देशों की तो पहले रफ्तार रुकेगी जो इन देशों पर तेल और गैस के लिए निर्भर हैं लेकिन संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन जैसे खाड़ी देशों की सांसें भी रुकने लगेंगी क्योंकि होर्मुज जलडमरूमध्य होकर गुजरने वाला समुद्री रास्ता इन देशों के लिए जीवन रेखा है।

एक शांत दिखने वाली विदाई से हुई भारी क्षति!

हरीश गुप्ता

भाजपा ने असम, ओडिशा और बिहार में राज्यसभा की तीन अतिरिक्त सीटें जीतीं, लेकिन फिर हरियाणा में उसे करारा झटका लगा, जहां वह एक सीट एक वोट से भी कम अंतर से हार गई। क्या यह महज एक सांख्यिकीय गड़बड़ी थी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजनीति में मुद्दे शायद ही कभी हमेशा के लिए दफन होते हैं। जगदीप धनखड़ को ही देख लीजिए। बड़े धूमधाम से उपराष्ट्रपति पद पर आसीन हुए धनखड़ के अचानक बाहर निकलने से पार्टी ने उन्हीं एक तरह से बंद अध्याय मान लिया था। न तो अदालत में वापसी (परंपरा इसकी इजाजत नहीं देती), न ही दोबारा चुनाव – राजनीतिक रूप से उनका अस्तित्व ही धूमिल हो गया। या कम से कम ऐसा ही लग रहा था।

लेकिन राजनीति में टाइमिंग बहुत ही विचित्र होती है। बिना चुनाव लड़े, प्रचार किए या यहां तक कि भाषण दिए भी, धनखड़ ने चुपचाप राज्यसभा की एक सीट अपने पक्ष में कर ली। इसका सुराग हरियाणा और देवी लाल की विरासत के उत्तराधिकारी अभय चौटाला तक जाता है। इस्तीफे के बाद से चौटाला के फार्महाउस में धनखड़ रह रहे हैं – मेहमान के तौर पर नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य की तरह।

जब मतदान हुआ तो इंडियन नेशनल लोक दल (आईएनएलडी) ने अपने दो विधायकों के साथ किसी से गठबंधन करने के बजाय मतदान से परहेज किया। उनकी चुप्पी ने बहुत कुछ कह दिया। अगर ये वोट भाजपा के पक्ष में जाते तो शायद यह ‘हारी हुई’ सीट उन्हें मिल जाती। यहीं पर गणित और भावना का टकराव होता है। भाजपा के अंदरूनी हलकों में यह चिंता बढ़ती जा रही है कि ‘धनखड़ फैक्टर’ कोई एक बार की घटना नहीं है। खबरों के मुताबिक, उनके अचानक बाहर होने से जाट समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं – न सिर्फ हरियाणा में, बल्कि पूरे राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में।

जिस समुदाय ने कभी उनकी पदोन्नति को प्रतीकात्मक सशक्तिकरण माना था, अब वही उनके पतन को राजनीतिक उपेक्षा के रूप में देख रहा है। और एक ऐसे क्षेत्र में जहां जातिगत समीकरण अक्सर चुनावी बयानबाजी पर भारी पड़ते हैं, यह धारणा दूर-दूर तक फैल सकती है। इसका तत्काल नुकसान क्या है? एक राज्यसभा सीट। संभावित परिणाम एक धीमी, सुलगती राजनीतिक प्रतिक्रिया। क्योंकि भारतीय



राजनीति में, हमेशा जोरदार विदाई ही नुकसान नहीं पहुंचाती- कभी-कभी, चुपचाप हुई विदाई ही सबसे लंबे समय तक गुंजती है।

कभी अपनी दृढ़ता से कार्यवाही का संचालन करने वाले जगदीप धनखड़ को अब पता चल रहा है कि असली खेल तो कुर्सी छोड़ने के बाद ही शुरू होता है। पद छोड़ने के लगभग आठ महीने बाद भी, पूर्व उपराष्ट्रपति अपने एपीजे अब्दुल कलाम रोड स्थित आधिकारिक रूप से आवॉर्निट टाइप-8 बंगले में कदम रखने का इंतजार कर रहे हैं- जो दिल्ली के प्रमुख लुटियंस एस्टेट से से एक है। इसका कारण? मरम्मत, तकनीकी पेचीदगियां, कागजी कार्यवाही – आप अपनी पसंद का कोई भी नौकरशाही बहाना चुन सकते हैं। विडंबना स्पष्ट है। एक संवैधानिक प्राधिकारी, जो कभी व्यवस्था के शिखर पर था, अब उसी उलझन में फंसा है जिसकी शिकायत आम लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। यहीं बताया गया है कि आवंटन तो महीनों पहले हो चुका है।

लेकिन घर मानो लुका-छिपी खेल रहा है- खाली है, फिर भी अनुपलब्ध; आवॉर्निट है, फिर भी सौंपा नहीं गया है। कब्जे का औपचारिक पत्र भी मानो लंबे समय से गायब है। हमेशा भरोसेमंद रहने वाला केंद्रीय लोक निर्माण विभाग कथित तौर पर इस पर ‘काम’ कर रहा है-हालांकि वास्तव में किस काम पर काम हो रहा है, यह बंगले की चाबियों की तरह ही रहस्य बना हुआ है। इस बीच, धनखड़ एक निजी फार्महाउस में समय बिता रहे हैं, यह अस्थायी व्यवस्था एक लंबे किस्से में तब्दील होती जा रही है। दिल्ली के सत्ता गलियारों के भव्य रंगमंच में, यह आवास में देरी मात्र नहीं, बल्कि इस बात का एक ज्वलंत उदाहरण है कि व्यवस्था अपने ही अनुभवी लोगों के साथ कैसा व्यवहार करती है।

पूनम आई. कौशिश

संशोधित महिला आरक्षण विधेयक, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, विधेयक 2023 को लागू करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस अधिनियम में 2029 के आम चुनावों में महिलाओं को विधायिका में 33 प्रतिशत सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। विधेयक में संसद और विधानमंडल में महिला आरक्षण को वर्तमान में चल रही जगणना और परिसीमन की कवायद से अलग रखना है क्योंकि वर्तमान कानून के अंतर्गत 2029 के लोकसभा चुनावों से पूर्व जनगणना और परिसीमन की पूर्वापेक्षा को पूरा करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है।

सरकार की योजना है कि विधानसभाओं और लोकसभा की सदस्य संख्या 50 प्रतिशत तक बढ़ाई जाए, जिसके अंतर्गत लोकसभा को वर्तमान 543 सीटें बढ़कर 816 सीटें हो जाएंगी, जिसमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यदि यह विधेयक पारित होता है तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर, जिनमें 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, वे भी विधानसभा में महिला आरक्षण लागू कर सकते हैं। इसके साथ ही विस्तारित सदन में राज्यों का समानुपातिक प्रतिनिधित्व यथावत रहेगा और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए लॉटरी प्रणाली अपनाई जाएगी। तथापि इसके लिए परिसीमन आयोग के अधिकार क्षेत्र को बदलना होगा जो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए 2027 की जनगणना नहीं, अपितु 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाएगा क्योंकि 2027 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आने में विलंब होगा जिसके कारण 2029 में परिसीमन करने के लिए अत्यधिक विलंब हो जाएगा।

वर्तमान में दक्षिणी राज्य इस बात से चिंतित हैं कि वर्तमान जनसंख्या के आधार पर परिसीमन से लोकसभा में समानुपातिक प्रतिनिधित्व के संदर्भ में उन्हें नुकसान होगा क्योंकि इन राज्यों में उत्तरी और पूर्वी राज्यों की तुलना में जनसंख्या नियंत्रण के उपाय कुशलता से लागू किए गए हैं। दक्षिणी राज्यों की चिंता को दूर करने के लिए प्रत्येक राज्य में सीटों का हिस्सा वर्तमान स्तर पर रखा जाएगा। दक्षिणी

पदनाम फोके पड़ जाते हैं, नियम-कानून शिथिल हो जाते हैं,

और फाइल-हमेशा फाइल ही रहती है- अपने आप में एक अलग ही रूप ले लेती है। धनखड़ के लिए, यह सबक शायद अप्रत्याशित है, लेकिन सुस्पष्ट है- दिल्ली में, आप एक बार नियमों को लागू कर सकते हैं-लेकिन देर-सवेर, आपको उनका शिकार भी होना पड़ता है।

नीतीश नहीं छोड़ेंगे सत्ता की बागडोर !

खराब स्वास्थ्य और सत्ता परिवर्तन की अटकलों के बावजूद, नीतीश कुमार एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं: वे बिहार की राजनीतिक दुनिया से जल्द विदा नहीं होने वाले हैं। राज्यसभा में जाने की तैयारी के बावजूद जनता दल (यूनाइटेड) की अध्यक्षता बरकरार रखने का उनका कदम पीछे हटना नहीं, बल्कि रणनीति में बदलाव का संकेत है।

एनडीए के भीतर यह संदेश साफ है कि नीतीश मुख्यमंत्री की कुर्सी से हट सकते हैं, लेकिन सत्ता की बागडोर नहीं छोड़ेंगे। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का मानना ​​है कि उत्तराधिकारी के चयन में उनकी भूमिका निर्णायक होगी। सम्राट चौधरी का नाम चर्चा में है, लेकिन अंतिम निर्णय नीतीश का ही होगा।

उपमुख्यमंत्री के प्रति उनके बार-बार सार्वजनिक समर्थन को पार्टी को तैयार करने और नियंत्रण बनाए रखने, दोनों ही तरह से देखा जा रहा है। निशांत कुमार का सुनियोजित उदय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कभी राजनीति से दूर रहे युवा कुमार को अब भावी हितधारक के रूप में स्थापित किया जा रहा है-

यह विकास नीतीश की सत्ता पर नियंत्रण छोड़े बिना अपने बाद के युग को आकार देने की मंशा को रेखांकित करता है। भाजपा के लिए, यह व्यवस्था टकराव के बिना निरंतरता प्रदान करती है। जेडीयू के लिए, यह सुनिश्चित करती है कि उसका सामाजिक गठबंधन- विशेष रूप से ‘लव-कुश’ गठबंधन- एक परिचित धुरी पर टिका रहे। स्वास्थ्यगत सीमाएं हो सकती हैं, लेकिन इससे नीतीश की राजनीतिक सुझबूझ कम नहीं हुई है।

प्रासंगिकता छोड़ने के बजाय भूमिकाएं बदलकर, वह एक ऐसा सहज रास्ता बना रहे हैं जो उन्हें बिहार की सत्ता संरचना के केंद्र में मजबूती से बनाए रखता है। बिहार की राजनीति में, नीतीश गायब नहीं हो रहे हैं- वे केवल मंच पर अपनी स्थिति बदल रहे हैं।



अगले 25-30 वर्षों के लिए वर्तमान स्तर पर यथावत रखना और दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 82 में संशोधन के लिए विधेयक लाना, जिसमें प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा की सीटों का समायोजन किया जाएगा। इस संदर्भ में गृह मंत्री अमित शाह ने राजग के सहयोगी दलों और विपक्षी दलों तुणमूल और वामपंथी दलों के साथ पिछले सप्ताह परामर्श किया, जिसमें कांग्रेस शामिल नहीं थी और प्रस्ताव कि्या कि विधानमंडलों में लगभग 50 प्रतिशत सीटों को बढ़ा दिया जाए जिससे वर्तमान सांसदों और विधायकों को अपनी सीट बचाएं हैं और साथ ही महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण भी किया जाएगा।

भाजपा के एक मंत्री के अनुसार महिलाओं की दशा में सुधार के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाने की अत्यावश्यकता है क्योंकि पंचायतों के बारे में किए गए अद्यतन अध्ययनों के अनुसार जहां पर महिला आरक्षण लागू है वहां पर महिलाओं की राजनीति में भागीदारी, नेतृत्व, महिला सशक्तिरण और संसाधनों के आबंटन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। हालांकि महाराष्ट्र से बिहार तक अनेक राज्यों में महिलाओं के चुनाव जीतने के बावजूद पुरुष उनके प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर रहे हैं। देश की जनसंख्या में महिलाओं की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है और उन्होंने अनेक राज्यों में चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाई है तथा बिहार इसका उदाहरण है। इन सीटों पर विपक्ष की बजाय भाजपा को अधिक जीत मिली है।

वर्तमान में जब हम महिलाओं के सशक्तिकरण करने की बात करते हैं तो हमें कुछ कटु सच्चाइयों को भी देखना

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जाना तय

सनत जैन

दुनिया का सबसे ताकतवर देश, अमेरिका इस वक अपने देश और वैश्विक स्तर पर दोनों तरफ से भारी दबाव में नजर आ रहा है। एक तरफ पश्चिम एशिया में ईरान के साथ लड़ाई जारी है, दूसरी तरफ देश के अंदर ही ट्रंप के खिलाफ लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है और लोग सड़कों पर उतर आए हैं। शनिवार को अमेरिका के सभी 50 राज्यों में बड़े पैमाने पर 3300 से ज्यादा स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों का नाम था- नो किंग्स देश में कोई राजा नहीं चलेगा। लोकतंत्र में राजा जनता है। अमेरिका ही नहीं बल्कि यूरोप, लैटिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विरोध हो रहा है। सवाल उठता है, आधिकारक यह आंदोलन किनना बड़ा है? ट्रंप के खिलाफ विरोध की यह तीसरी बड़ी लहर है। इससे पहले भी लाखों लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। इस बार का आंकड़ा सबसे बड़ा है। अमेरिका के सभी राज्यों में इस आंदोलन की आग फैल गई है। 3300 से ज्यादा जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इस आंदोलन की खास बात यह है, यह शहरों के साथ-साथ गांवों में भी देखने को मिला है। लोगों ने खुलकर अपना विरोध जताया है। इस बार सबसे बड़ा विरोध मिनसोटा की राजधानी सेंट पॉल में हुआ। जहां मशहूर सिंगर ब्लस प्रिंस्टीन ने भी आंदोलन में भाग लिया, और एक खास गाना गाया। जो हाल की एक दुखद घटना से जुड़ा हुआ था। उनके साथ कई बड़े सेलिब्रिटी जिसमें एक्टर्स, नेता और सामाजिक कार्यकर्ता भी आंदोलन के मंच पर नजर आए। सवाल उठता है, अमेरिका और आस-पास के देश के लोगों में आखिर किस बात का गुस्सा भरा है? प्रदर्शन करने वालों के पास कम प्रशानन की शिकायतों की लंबी फेहरिस्त थी। सबसे ज्यादा नाराजगी ट्रंप सरकार को इमीग्रेशन नीति को लेकर है। लोगों का मानना ​​है, सख्ती और ग्रेपेमारी से आम लोग डर और भय के साथ जी रहे हैं। इसके अलावा ईरान के साथ चल रहे संघर्ष का विरोध, ट्रॉसजेंडर के अधिकारों में कटौती, अमीर-गरीब के बीच बढ़ती खाई जैसे मुद्दों पर लोगों ने खुलकर आवाज उठाई है। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और सैंडियागो जैसे शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। बैनर और नारों के साथ सरकार के खिलाफ यहां पर भारी गुस्सा दिखा। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के असर की बात की जाए, तो यह विरोध अमेरिका तक सीमित नहीं रहा। यूरोप के कई देशों में लोग इसी तरह के संदेश के साथ ट्रंप के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं। कहीं तानाशाही के



खिलाफ तो कहीं नुस्रे के खिलाफ नारे लगे। यूरोप के देशों में अच्छीखासी भीड़ सड़कों पर देखने को मिली। रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने भी हाल ही में बैकड से बहिष्कार कर ट्रंप की नीतियों का विरोध किया। ट्रंप समर्थकों का कहना है, इन प्रदर्शनों को ज्यादा अहमियत नहीं है। उनका कहना है कि यह सब राजनीतिक एजेंडा है। ट्रंप के विरोध में जो तस्वीर जमीन पर दिख रही है, उसके अनुसार जिस तरह संसद और रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों और विशिष्ट वर्ग में राष्ट्रपति ट्रंप का विरोध बढ़ रहा है। उनके ऊपर हाल ही में इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप लगे हैं। संसद से अनुमति लिए बिना ट्रंप ने यह युद्ध छोड़ा है। जिसके कारण वह संसद में अलग-थलग पड़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कुछ ऐसे राज्यों में भी प्रदर्शन हुए हैं, जहां ट्रंप को भारी समर्थन मिला था। अमेरिका में माहौल इन दिनों काफी गर्म है। पिछले कुछ महीनों में महंगाई काफी तेजी के साथ बढ़ी है। अमेरिका एक तरफ बाहरी तनाव, दूसरी तरफ आंतरिक विरोध से जूझ रहा है। दोनों स्थितियों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिन-प्रतिदिन कमजोर होते चले जा रहे हैं। आने वाले समय में यह आंदोलन किस दिशा में जाएगा, यह देखना अहम होगा। अमेरिका और इजरायल ने जिस तरह से ईरान पर आक्रमण किया है, इसका असर अब सारी दुनिया के देशों पर पड रहा है। ट्रंप की नीतियों के कारण डोलार मुद्रा और पेट्रोल डॉलर व्यापार को काफी नुकसान हुआ है जिसका असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। ट्रंप के समय में कर्ज भी तेजी के साथ बढ़ा है। महंगाई और बेरोजगारी के कारण आम नागरिक बहुत परेशान हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की इमेज साइको के रूप में देखने को मिल रही है। जिसके कारण राजनीतिक क्षेत्र में कहा जा रहा है, कि डोनाल्ड ट्रंप शायद ही अपना कार्यकाल पूरा कर पाएं। जिस तरह से उन्होंने अमेरिका को मुसीबत में फंसाया है। डेमोक्रेटिक के साथ-साथ रिपब्लिकन सांसद भी उनके विरोध में खड़े हो रहे हैं। जिसके कारण ज्यादा दिनों तक राष्ट्रपति पद पर बने रहना उनके लिए आसान नहीं होगा।



सिंगापुर की गलियों में बसा मौनी रॉय का दिल, बोलीं

शूटिंग करने आई थीं, लेकिन शहर के आकर्षण में खो गई

फिल्म और म्यूजिक की दुनिया में अक्सर शूटिंग लोकेशन कलाकारों के लिए बेहद खास होती है। ऐसा ही कुछ अनुभव अभिनेत्री मौनी रॉय ने किया, जब उन्होंने सिंगापुर में अपने नए म्यूजिक वीडियो 'साँसी' की शूटिंग की। इस गाने में उन्होंने पंजाबी सिंगर-रैपर रियार साब और मशहूर रैपर डिवाइन के साथ काम किया है। मौनी रॉय ने अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया कि सिंगापुर पहले से ही उनकी ट्रेवल लिस्ट में था, लेकिन इस बार वहां जाना उनके लिए बेहद खास बन गया। उन्होंने कहा, "इस खूबसूरत देश को पहली बार एक्सपीरियंस करना और उसी दौरान शूटिंग करना मेरे लिए एक अनोखा अनुभव था। मुझे वहां का खाना, फैशन और माहौल बेहद अच्छा लगा। मैं खुद को

उस माहौल में पूरी तरह घुली हुई महसूस कर रही थी।" मौनी ने कहा, "शूटिंग के दौरान मैं शहर के अलग-अलग हिस्सों में गई और हर जगह का अलग ही अनुभव था। कभी शहर बहुत तेज रफ्तार और हलचल भरा लगता था, तो कभी शांत और सुकून देने वाला। धीरे-धीरे मुझे इस शहर से एक खास जुड़ाव महसूस होने लगा। मैं यहां काम करने आई थी, लेकिन इस शहर के आकर्षण में कहीं खो सी गई। मैं दोबारा जरूर सिंगापुर आना चाहूंगी।" गाना 'साँसी' गली गैंग एंटरटेनमेंट के बैनर तले तैयार किया गया है और यह डिवाइन के पांचवें स्टूडियो एल्बम 'वॉकिंग ऑन वॉटर' का हिस्सा है। डिवाइन ने इस गाने को लेकर कहा कि वह एक ऐसा ट्रैक बनाना चाहते थे जिसे लोग आसानी से सुन सकें और अच्छा



महसूस करें। यह गाना एक अलग तरह की वाइब देता है, जिसमें म्यूजिक और एनर्जी दोनों हैं।

उन्होंने कहा, रियार साब के साथ मेरी केमिस्ट्री हमेशा अच्छी रही है और मौनी रॉय के साथ काम करने से यह प्रोजेक्ट और भी खास बन गया। जब शूटिंग के लिए लोकेशन तय की जा रही थी, तो सिंगापुर सबसे सही जगह लगा। मुझे इस शहर की तेज रफ्तार अंदाज काफी पसंद आया।

वहीं, रियार साब ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, डिवाइन के साथ काम करना हमेशा आसान और मजेदार होता है। 'साँसी' ऐसा गाना है जिसमें शुरुआत से ही सही एनर्जी थी। सिंगापुर में शूटिंग करना एक

अलग और खास अनुभव था। हमने इस गाने में अपना पंजाबी अंदाज जोड़ने की कोशिश की है, ताकि लोग इसे सुनकर एंजॉय कर सकें।

हर पहलू में एक अद्भुत फिल्म, विकी कौशल ने आदित्य धर की पूरी टीम को बताया धुरंधर

स्पष्ट ई एक्शन थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' का खुमार हर किसी के सिर चढ़कर बोल रहा है। हर कोई फिल्म की सराहना किए बिना नहीं रह पा रहा है। इसी बीच मशहूर अभिनेता विकी कौशल और प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म

काम बहुत मजेदार था। वहीं, शिवकुमार की एडिटिंग को विकी ने अब तक का सबसे बेहतरीन काम बताया, जबकि उन्होंने खुद को संगीतकार शाश्वत सचदेव का फैन बताया। इसी के साथ ही, विकी ने पूरी टीम को बधाई देते हुए लिखा, जियो स्टूडियोज, ज्योति देशपांडे, लोकेश धर और बी62 स्टूडियोज को बधाई। पूरी



की पूरी टीम की जमकर सराहना की है। अभिनेता ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक नोट पोस्ट किया। उन्होंने आदित्य समेत सभी की जमकर सराहना करते हुए फिल्म की पूरी टीम को धुरंधर जैसे शब्द से संबोधित किया। अभिनेता ने लिखा कि फिल्म देखकर उन्हें काफी हैरान, खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। अभिनेता ने निर्देशक आदित्य धर की मेहनत, ईमानदारी और शानदार काम की खूब प्रशंसा की। अभिनेता ने लिखा, आदित्य भाई, आपने जिस तरह से फिल्म बनाई है, वह सोने के समान है। आपको इस सफलता के लिए बधाई। विकी ने रणवीर सिंह की भी जमकर सराहना की। उन्होंने लिखा, रणवीर सिंह, आप मुझे हमेशा प्रेरित करते हैं। एक अभिनेता के रूप में आपकी कला और अंदाज बहुत बेहतरीन है। आर. माधवन सर को देखकर अच्छा लगा और राकेश बेदी सर को देख सारा प्यार। मुस्तफा अहमद का

टीम ने शानदार काम किया है। आप सभी सच में 'धुरंधर' हैं। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने भी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर धुरंधर का पोस्टर शेयर कर नोट लिखा, रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, सारा अर्जुन, राकेश बेदी और आदित्य धर। आप सभी को दिल से बधाई। आदित्य, आप सच में एक मिशन के साथ काम करने वाले इंसान हैं। 'धुरंधर' हर पहलू में एक अद्भुत फिल्म है। आप सभी की कला, मेहनत और समर्पण के लिए धन्यवाद। 'धुरंधर: द रिवेंज' का निर्देशन आदित्य धर ने किया है। यह साल 2025 में आई फिल्म 'धुरंधर' का दूसरा भाग (सीकल) है। फिल्म का पहला हिस्सा अच्छा था, लेकिन इस बार कहानी और एक्शन दोनों को और ज्यादा दमदार बना दिया गया है, जिसकी वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी कमाई कर रही है।

शरद केलकर ने बताया कैसे छोटे प्रैंक बनाते हैं काम के माहौल को पॉजिटिव



ही रूप सामने आता है। मैं अपने करीबी दोस्तों और परिवार पर अक्सर प्रैंक करता रहता हूँ। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया, "पिछले कुछ सालों में मैंने कई बार अपने दोस्तों और घरवालों के साथ ऐसे मजेदार प्रैंक किए हैं, जिनकी याद आज भी मुझे हंसा देती है। जब सामने वाले की अचानक प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, तो वह पल बहुत खास होता है। मैंने कभी भी ऐसा कोई प्रैंक नहीं किया, जिससे किसी की भावना को ठेस न पहुंचे।" शरद ने कहा, "शूटिंग सेट पर भी मैं इसी तरह का माहौल बनाए रखने की कोशिश करता हूँ। मेरा मानना है कि टीवी शो की शूटिंग में कलाकारों और टीम को कई-कई घंटों तक साथ काम करना पड़ता है, ऐसे में अगर माहौल बहुत ज्यादा गंभीर हो जाए तो थकान और तनाव बढ़ सकता है। इसलिए मैं बीच-बीच में हल्के-फुल्के मजाक से सकारात्मकता बनाए रखता हूँ। ऐसे छोटे-छोटे पल ही टीम के बीच बेहतर तालमेल और दोस्ती को मजबूत करते हैं।" शरद ने आगे कहा, "अप्रैल फूल डे सिर्फ एक दिन नहीं है, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में हंसी और मस्ती कितनी जरूरी है। अगर मजाक दिल से और अच्छे इरादे से किया जाए, तो यह हर दिन का हिस्सा होना चाहिए।"

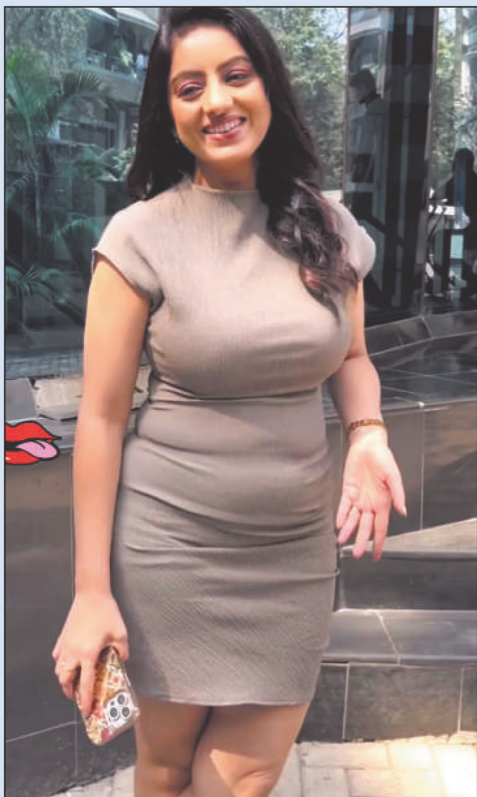
टीवी इंडस्ट्री के जाने-माने अभिनेता शरद केलकर ने सशक्त किरदारों के चलते दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। लेकिन उनमें एक गंभीर कलाकार की छवि के पीछे एक मजाकिया और शरारती व्यक्तित्व भी छुपा हुआ है, जिसका खुलासा उन्होंने अप्रैल फूल डे के मौके पर किया। शरद ने बताया कि असल जिंदगी में वह काफी मस्ती करने वाले इंसान हैं। शरद ने कहा, लोग मुझे देखकर अक्सर यही मान लेते हैं कि मैं हर समय बहुत गंभीर रहता हूँ, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। काम के दौरान मैं अपने किरदार को लेकर बेहद फोकस्ड और प्रोफेशनल रहता हूँ, लेकिन जैसे ही कैमरा बंद होता है, मेरा एक अलग

ये नया सफर जरूर धमाल मचाएगा, मंगल-देश की बेटी के लिए दीपिका सिंह को फैस ने दी बधाई

भारतीय टेलीविजन की दुनिया में कई शो होते हैं जो दर्शकों के दिल में अपनी खास जगह बना लेते हैं। ऐसे ही शो में से एक है 'मंगल लक्ष्मी', जो अब अपने नए अध्याय 'मंगल-देश की बेटी' के साथ दर्शकों के सामने आ रहा है। इस नई कहानी में मुख्य किरदार मंगल नई जिम्मेदारियों और चुनौतियों का सामना करती हैं। अभिनेत्री दीपिका सिंह ने इस नई यात्रा को लेकर इंस्टाग्राम पर एक भावपूर्ण पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपनी खुशी, उत्साह और टीम के प्रति आभार जताया। दीपिका ने अपने पोस्ट में लिखा कि वह इस नए चैप्टर को लेकर पूरी तरह से अभिभूत और उत्साहित हैं। उन्होंने दर्शकों को बताया कि इस कहानी में मंगल को देश की सेवा का अवसर

मिलता है और वह खुद को विशेष महसूस करती हैं। दीपिका ने अपने कैप्शन में लिखा, "'मंगल-देश की बेटी' के इस नए सफर को निभाने के लिए मैं बेहद खुश, रोमांचित और उत्साहित हूँ।" उन्होंने अपने पोस्ट में टीम का भी धन्यवाद किया। दीपिका ने कहा कि पिछले 700 एपिसोड्स के दौरान पूरी टीम ने लगातार मेहनत और समर्पण दिखाया। उन्होंने बताया कि दर्शकों का समर्थन ही उनकी इस सफलता की सबसे बड़ी वजह है। उन्होंने अपने फैस से हर एपिसोड देखने की अपील करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वे सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे इस शो का आनंद लेते रहेंगे। दीपिका के इस पोस्ट पर कई लोगों ने

कमेंट्स किया। एक ने लिखा, 'दीपिका जी, आपका नया किरदार देखकर बहुत खुश हूँ। मंगल का यह रूप बहुत प्रेणोदायक लग रहा है।' दूसरे फैस ने लिखा, 'आपकी मेहनत और एनर्जी सच में कमाल की है।' अन्य ने लिखा, 'शो देखने के लिए अब और भी उत्साहित हो गए हैं, ये नया सफर जरूर धमाल मचाएगा।' 'आपकी एक्टिंग हमेशा दिल को छूती है।' 'मंगल लक्ष्मी' कन्नड़ टीवी सीरीज 'भाग्यलक्ष्मी' का आधिकारिक रूपांतरण है। इस शो में दीपिका के अलावा सनिखा अमित, नमन शर्मा और शुभम दीप्ता मुख्य कलाकार हैं। इस कहानी में मंगल अपनी बहन लक्ष्मी के लिए सही जीवनसाथी खोजती हैं।



सुबह सही तो सब सही, सामंथा रूथ प्रभु ने शेयर किया अपना पावर मॉर्निंग रूटीन

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग फिटनेस, स्किन और मानसिक शांति के लिए कई तरीके अपनाते हैं, लेकिन अक्सर छोटी-छोटी आदतों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसको लेकर अब अभिनेत्री सामंथा रूथ प्रभु ने अपनी 'पावर मॉर्निंग' रूटीन साझा की है। उन्होंने बताया कि कैसे सही तरीके से दिन की शुरुआत करने से न सिर्फ शरीर बल्कि दिमाग पर भी सकारात्मक असर पड़ता है। सामंथा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि उन्होंने कई तरह की मॉर्निंग रूटीन आजमाई हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें एक ऐसा आसान तरीका मिला जो उनके लिए सबसे ज्यादा असरदार साबित हुआ। उन्होंने इसे 'पावर मॉर्निंग' नाम दिया। सामंथा ने कहा, "अगर सुबह सही तरीके से शुरू होती है, तो पूरा दिन सबकुछ सही होता है। ऊर्जा अपने आप बेहतर हो जाती है।"

वीडियो में सामंथा ने कहती है, "कई बार लोग सब कुछ सही करने के बावजूद भी पेट की चर्बी कम नहीं कर पाते, स्किन की समस्याएं बनी रहती हैं या सुबह उठते समय चेहरा सूजा हुआ लगता है। इसकी एक बड़ी वजह गलत मॉर्निंग रूटीन हो सकती है। इसलिए लोगों को अपनी सुबह की आदतों पर ध्यान देना जरूरी है।"

सामंथा ने खासतौर पर स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल के बारे में बात की। उन्होंने कहा, "सुबह उठते ही शरीर में कॉर्टिसोल का स्तर ज्यादा होता है, जो सामान्य है। लेकिन अगर हम उठते ही फोन, न्यूज या काम देखने लगते हैं, तो यह स्ट्रेस और बढ़ जाता है। इससे दिनभर ध्यान कम रहता है।"

अपनी रूटीन को विस्तार से बताते हुए सामंथा ने सबसे पहला नियम बताया कि उठने के बाद एक घंटे तक फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद कुछ मिनट शांति में बैठकर गहरी सांस लेनी चाहिए। इससे दिमाग को संकेत मिलता है कि आप सुरक्षित हैं, जिससे शरीर बेहतर तरीके से काम करता है और हेल्थ पर अच्छा असर पड़ता है।

इसके अलावा, उन्होंने कहा, "उठने के 10 मिनट के अंदर चेहरे पर धूप लेना फायदेमंद होता है। साथ ही एक हेल्दी ड्रिंक और संतुलित नाश्ता ब्लड शुगर को कंट्रोल रखता है।"

इस वीडियो के कैप्शन में सामंथा ने लिखा, इस रूटीन को बनाने में मुझे कई साल लगे, लेकिन इसका असर मेरी जिंदगी पर गहराई से पड़ा है। आप 21 दिनों तक इस रूटीन को लगातार अपनाएं। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर आप इसे जारी रखते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि आप अपनी जिंदगी को कितना बदल सकते हैं।

तेलंगाना सीएम रेड्डी ने यूडीएफ का जारी किया घोषणापत्र

कोच्चि। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे (यूडीएफ) ने गुरुवार को केरल विधानसभा चुनावों के घोषणापत्र जारी किया।

कोच्चि में आयोजित कार्यक्रम में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस दस्तावेज को जारी किया, जहां गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। यह मैनिफेस्टो साफ तौर पर चुनाव में मजबूत दावेदारी का संकेत देता है। दरअसल, केरल में 9 अप्रैल को 140 नए विधायकों के चुनाव के लिए मतदान होगा। घोषणापत्र के केंद्र में मिशन समुद्र है, जो केरल को उसकी 600 किलोमीटर लंबी तटरेखा, 44 नदियों और बंदरगाहों के नेटवर्क का लाभ उठाकर एक वैश्विक समुद्री केंद्र में बदलने की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस परियोजना में माल दुलाई, यात्री सेवाओं और पर्यटन को एकीकृत करने वाले एक चरणबद्ध जल परिवहन ग्रिड का प्रस्ताव है, जो एक एकीकृत तटीय लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र में परिणत होगा।

एलडीएफ ने केरल विस चुनाव के लिए घोषणापत्र जारी किया

तिरुवनंतपुरम। केरल की सत्ताधारी वामपंथी दल (एलडीएफ) ने गुरुवार को विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया, जिसमें राज्य भर में लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से

कल्याणकारी और विकासात्मक उपायों का मिश्रण पेश किया गया है। इस घोषणापत्र को मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन ने यहां जारी किया। घोषणापत्र की मुख्य बातों में राज्य में घोर गरीबी उन्मूलन का संकल्प, कल्याणकारी पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह करना और स्थानीय स्तर पर उचित स्वास्थ्य सेवा और सहायता प्रणाली सुनिश्चित करने के प्रयास शामिल हैं। वामपंथी सरकार ने हाल ही में घोषणा की थी कि राज्य में घोर गरीबी को समाप्त कर दिया गया है और कल्याणकारी पेंशन को 1600 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया है। युवाओं के लिए, घोषणापत्र में रोजगार पर जोर दिया गया है। इसमें पढ़ाई पूरी कर रहे छात्रों के लिए कैंपस प्लेसमेंट और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विस्तार का वादा किया गया है।

उदयनिधि स्टालिन ने चेपाॅक से नामांकन दाखिल किया

चेन्नई। तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने गुरुवार को चेपाॅक-थिरुवल्लिकेनी निर्वाचन क्षेत्र के लिए द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री एम.के.

स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन ने नामांकन पत्र जमा करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय जाते समय रोड शो किया। ये चेपाॅक-थिरुवल्लिकेनी से मौजूदा विधायक हैं और एआईएडीएमके उम्मीदवार अधिराजराम के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि हम इतिहास रचेंगे, हम इस बार निश्चित रूप से जीतेंगे। हमारे नेता दूसरी बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनेंगे। 2021 के चुनावों में, डीएमके उम्मीदवार ने पट्टाली मक्कल कच्ची (पीएमके) उम्मीदवार एवीए कसाली को 69,355 वोटों के अंतर से हराया। बुधवार को उदयनिधि स्टालिन ने 8,000 रुपये के कूपन देने की योजना की घोषणा की थी।

असम की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री

गुवाहाटी। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इतेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की कथित मनमानी पर निशाना साधते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों के

माध्यम से उन्हें एक स्पष्ट संदेश भेजा जाना चाहिए। गुवाहाटी में एक चुनावी रैली के दौरान ओवैसी ने कहा कि हालात बेहद खराब हैं। और इस स्थिति में दमनकारी ताकतों से निपटने के लिए एआईएमआईएम के माध्यम से मुस्लिम समुदाय के नेतृत्व को मजबूत करना जरूरी है। लोकतंत्र में सिर्फ नारे लगाने से काम नहीं चलता। हमें मतदान के माध्यम से यह सुनिश्चित करना होगा कि हिमंता बिस्वा सरमा को उनकी प्रतिगामी राजनीति का स्पष्ट संदेश मिले। ओवैसी ने आगे कहा कि इसे रोकने के लिए हमें एकजुट रहना होगा। चुनाव के दिन मतदान करके आपको जवाब देना होगा। लोकतंत्र में आपका वोट एक शक्तिशाली हथियार है - अपनी अंतरात्मा और राजनीतिक जागरूकता का इस्तेमाल करें।

गुजरात में मिनी आम चुनाव का बिगुल, 26 को मतदान

गांधीनगर। गुजरात राज्य निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि स्थानीय निकाय चुनाव 26 अप्रैल को होंगे। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता तत्काल

लागू हो जाएगी, जिसे व्यापक रूप से मिनी आम चुनाव कहा जा रहा है। मतगणना 28 अप्रैल को होगी। ये चुनाव सूरत, राजकोट, वडोदरा, भावनगर, जामनगर, कच्छ, वलसाड और वापी सहित 15 नगर निगमों में होंगे। इसके अलावा, 34 जिला पंचायतों, 260 तालुका पंचायतों और 84 नगर पालिकाओं में भी मतदान होगा, जो गुजरात के शहरी और ग्रामीण शासन प्रणालियों का पूर्ण नवीनीकरण दर्शाता है। अधिकारियों ने बताया कि गुजरात में कुल 9,992 सीटों पर 41.8 करोड़ से अधिक मतदाता अपने प्रतिनिधियों को चुनने के पात्र होंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी समय-सीमा के अनुसार, औपचारिक चुनावी प्रक्रिया अगले सोमवार, 6 अप्रैल को नामांकन चरण के साथ शुरू होगी।

पश्चिम एशिया संकट पर बोले राजनाथ सिंह

किसी भी हालात का सामना करने को भारत तैयार

तिरुवनंतपुरम। केरल विधासभा चुनाव के मधेनजर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को राज्य में प्रचार की कमान संभाली। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में ईंधन या गैस की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी ऊर्जा संकट से निपटने के लिए तैयार है।

केरल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय नौसेना हमारे टैंकरों को होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित रूप से ला रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के हितों की रक्षा के लिए अपनी कूटनीतिक कुशलता का इस्तेमाल कर रहे हैं।

राजनाथ सिंह ने कहा, आज हम सभी बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। पश्चिम एशिया में बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है। केरल के बहुत सारे लोग इन देशों में रहते हैं और काम करते हैं, लेकिन हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने भारतीय नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने में पीछे नहीं रहेंगे। इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं।

उन्होंने आगे कहा, कुछ लोग पश्चिम एशिया के इस संघर्ष के कारण झूठ फैलाकर तनाव फैलाना चाहते हैं। न तो देश में पेट्रोल-डीजल की कमी है, न तो गैस की कमी है और भारत किसी भी संकट से निपटने के लिए तैयार है। हमारी नौसेना स्टेट ऑफ होर्मुज से भारतीय टैंकरों को सुरक्षित तरीके से निकाल रही है, जबकि विश्व इस संकट के समय देश के साथ खड़े होने के बजाय निम्न स्तर की राजनीति कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा, मैंने देश के गृह मंत्री के रूप में भी काम किया है और आज मैं रक्षा मंत्री के रूप में देश को अपनी सेवा दे रहा हूं। पिछले 11 वर्षों में चाहे वो आंतरिक सुरक्षा की बात रही हो या चाहे बाहर के दुश्मनों से सुरक्षा की बात रही हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमारी



राष्ट्रीय सुरक्षा को ताकत दी है। ये बदलाव पूरी दुनिया को हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखने को मिला है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पड़ोसी द्वारा किसी भी प्रकार के दुस्साहस को अंजाम देने की स्थिति में निर्णायक कार्रवाई की कड़ी चेतावनी जारी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि मौजूदा हालात में हमारा पड़ोसी कोई भी दुस्साहस कर सकता है। अगर वह ऐसा करता है, तो भारत की कार्रवाई अभूतपूर्व और निर्णायक होगी। उन्होंने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है।

उन्होंने कहा, जब कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार का शासन था तो कैसे हालात थे याद कीजिए। आए दिन कोई न कोई घटना होती थी। जब से केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार आई है, आतंकवादी घटनाओं पर न केवल लगाम लगी है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ हमने निर्णायक कदम भी उठाए हैं। पश्चिम एशिया संकट पर राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत पश्चिम एशिया की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है।

असम सीएम हिमंता बिस्वा सरमा पर बरसे राहुल गांधी

गुवाहाटी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने

गुरुवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा को भारत का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताते हुए आरोप लगाया कि सरमा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय

गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिलकर राज्य में भूमि एटीएम चला रहे हैं, जिसके तहत वे जनता से जमीन छीनकर बड़ी कंपनियों को जमीन दे रहे हैं। बोकाजन निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार रतन एंटी के समर्थन में आयोजित एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि लोकप्रिय गायक जुबिन गार्ग असम और यहां की जनता के लिए खड़े थे, और कांग्रेस पार्टी राज्य में सत्ता में आने के 100 दिनों के भीतर उनकी मृत्यु के लिए न्याय दिलाएगी। राहुल ने कहा कि असम फूलों का एक गुलदस्ता है, जिसमें अलग-अलग धर्म, जाति और विचारधारा के लोग रहते हैं। कांग्रेस की सोच है- हिंदुस्तान की जनता के हाथ में असली ताकत हो, देश को चलाने में हर वर्ग को भागीदारी मिले। दूसरी तरफ भाजपा की विचारधारा है कि असम को दिल्ली से चलाया जाए- यही लड़ाई चल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 244 (ए) लेकर आई थी, क्योंकि हमारी सोच है कि असम को न गुवाहाटी से चलाया जाए और न दिल्ली से। 244 (ए) से असम की जनता को ताकत मिलती है और ये उन्हें फैसले लेने की शक्ति देता है। कांग्रेस और

भाजपा में यही फर्क है। भाजपा पर अपना हमला जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को ट्रंप कंट्रोल करता है। ट्रंप सरेआम नरेंद्र मोदी को गाली देता है। वो कहता है- नरेंद्र मोदी मुझे सर बुलता है। मैं उसका करियर कभी भी खत्म कर सकता हूं। उसका है है कि अडानी और एपस्टीन- ट्रंप ने इन दो हथियारों से नरेंद्र मोदी को पकड़ रखा है और मोदी कुछ नहीं कर सकते।



मालदा की घटना से ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका

पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई : सुप्रीम कोर्ट

नईदिल्ली। पश्चिम बंगाल में तुणमूल कांग्रेस के शासन को विपक्ष तो जंगलराज बताता ही है साथ ही समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की टिप्पणियों से भी राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते रहे हैं। अब दो चरणों में कराये जा रहे विधानसभा चुनावों के बीच उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था के पूरी तरह पटरी से उतरने संबंधी जो टिप्पणी की है वह ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार और उनकी पार्टी के लिए करारा झटका है। अदालत की टिप्पणी से ममता बनर्जी के शासन पर गंभीर सवाल उठे हैं। अदालत ने न केवल राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं, बल्कि इसे कानून व्यवस्था की पूर्ण विफलता बताते हुए शोष अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है।

हम आपको बता दें कि यह मामला उस समय सामने आया जब विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत मतदाता सूचियों की समीक्षा कर रहे सात न्यायिक अधिकारियों को मालदा जिले में कई घंटों तक घेर कर रखा गया। इनमें तीन महिला अधिकारी भी शामिल थीं। बताया गया कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे, उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए अधिकारियों को बाहर निकलने नहीं दिया। यह घटना दोपहर बाद शुरू हुई और देर रात तक चली, जिससे प्रशासन की तैयारी और तत्परता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस पूरे प्रकरण को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और सुनियोजित बताया। अदालत ने कहा कि यह केवल



विरोध नहीं था, बल्कि न्यायिक अधिकारियों को मानसिक रूप से डराने और चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास था। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

अदालत ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए? न्यायालय ने यह भी कहा कि यह राज्य सरकार और प्रशासन की ज़िम्मेदारी थी कि पहले से सूचना होने के बावजूद अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

इस घटना के बाद अदालत ने कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं। चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया है कि वह केंद्रीय बलों की तैनाती सुनिश्चित करे ताकि न्यायिक अधिकारी सुरक्षित माहौल में अपना कार्य कर सकें। साथ ही जिन अधिकारियों को खतरा महसूस हो रहा है, उनके घरों पर भी सुरक्षा व्यवस्था की जाए। अदालत ने यह भी कहा कि सुनवाई के दौरान भीड़ को सीमित रखा जाए और पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए जाएं।

हम आपको बता दें कि मालदा की घटना का विवरण काफी चिंताजनक है। विरोध प्रदर्शन कल्याचक क्षेत्र के एक कार्यालय के बाहर शुरू हुआ था, जहां लोगों ने अधिकारियों से मिलने की मांग की। अनुमति न मिलने पर भीड़ ने कार्यालय को घेर लिया और सड़कों को जाम कर दिया। इस दौरान कई स्थानों पर जनजीवन प्रभावित हुआ। देर रात जब अधिकारियों को निकाला गया तो उनके वाहनों पर पथराव और हमले की भी खबरें सामने आईं।

भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस घटना के लिए सीधे तौर पर राज्य सरकार को ज़िम्मेदार ठहराया है। उनका आरोप है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और मुख्यमंत्री के बयानों से माहौल और बिगड़ा है। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत बताया है। अब सवाल यह है कि इस फैसले का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों पर क्या असर पड़ेगा, देखा जाये तो यह घटना और अदालत की सख्त टिप्पणी राज्य सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। चुनावी माहौल में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, जिसका विपक्ष पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा।

देखा जाये तो सर्वोच्च न्यायालय की यह सख्ती एक संदेश भी है कि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा या डराने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राज्य सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है और इसका राजनीतिक समीकरणों पर कितना असर पड़ता है।

स्टेल

प्रमुख समाचार

साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज रासी वैन डर डुसेन लिया सन्यास

जोहानिसबर्ग। साउथ अफ्रीका के लिए करीब



8 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले दिग्गज बल्लेबाज रासी वैन डर डुसेन ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। साउथ अफ्रीका के लिए तीनों फॉर्मेट में खेल चुके रासी वैन डर डुसेन अब इंटरनेशनल क्रिकेट में नजर नहीं आएंगे। वहीं दो दिन पहले साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कंट्रैक्ट में रासी वैन डर डुसेन का नाम नहीं था। जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि बल्लेबाज ने इसी कारण से सन्यास का ऐलान किया है।

रासी वैन डर डुसेन ने साल 2018 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था और वे अब तक 18 टेस्ट, 71 वनडे इंटरनेशनल और 57 टी20 इंटरनेशनल मैच साउथ अफ्रीका के लिए खेले थे। आईपीएल का भी उनको अनुभव है। फरवरी में 37 साल के हुए रासी वैन डर डुसेन ने आखिरी इंटरनेशनल मैच साउथ अफ्रीका के लिए पिछले साल अगस्त में खेला था। इसके बाद से उनको टीम में जरूर शामिल किया गया, लेकिन प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिल पाई थी।

साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज ने इंस्टाग्राम के जरिए अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने लिखा कि, गर्व और शुक्रगुजार होते हुए मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट की घोषणा करता हूं। प्रोटियाज जर्सी पहनने के लिए हिम्मत और लगन की जरूरत होती है जो आपको परखती है और इनाम भी देती है। अपने देश के लिए खेलना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान रहा है। उन्होंने अपने फैसले, सपोर्ट स्टफ, कोच और मैनेजर समेत अपने परिवार को धन्यवाद कहा है।

उन्होंने साफ किया कि वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर जा रहे हैं, लेकिन घरेलू क्रिकेट खेलते रहेंगे और युवा खिलाड़ियों को मार्गदर्शन देंगे। डुसेन ने लिखा, प्रोटियाज के साथ मेरा सफर खत्म हुआ है, लेकिन क्रिकेट के साथ नहीं।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/

प्रमुख समाचार

2000 अंक उछला सेंसेक्स निफ्टी 22713 पर बंद

नईदिल्ली। एशियाई बाजारों से कमजोर रुख के बीच भारतीय शेयर बाजार गुरुवार (2 अप्रैल) को जोरदार रिकवरी लेते हुए बढ़त में बंद हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान पर हमले के ताजा बयान के बाद बाजार ने भारी गिरावट में शुुरुआत की। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स करीब 900 अंक की गिरावट लेकर 72,262 पर खुला। खुलते ही इंडेक्स में गिरावट और बढ़ गई और कारोबार के दौरान यह 71,545.81 अंक तक गिर गया था। लेकिन दोपहर के कारोबार में निचले स्तर से जबरदस्त रिकवरी देखी गई। अंत में सेंसेक्स 185.23 अंक या 0.25 प्रतिशत चढ़कर 73,319.55 पर बंद हुआ। इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी कमजोरी के साथ 22,383 पर खुला। कारोबार के दौरान यह 22,182 अंक तक फिसल गया था। अंत में यह 33.70 अंक या 0.15 फीसदी की बढ़त लेकर 22,713.10 पर बंद हुआ।

यूपीआई से लेनदेन मार्च में रिकॉर्ड स्तर पर

नई दिल्ली। त्योहारों और वित्त वर्ष की समाप्ति के कारण देश के लोकप्रिय भुगतान मंच यूपीआइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के जरिए होने वाले लेनदेन में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, मार्च महीने में लेनदेन का मूल्य 29.53 लाख करोड़ रुपए और संख्या 22.64 अरब के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। एनपीसीआई के अनुसार, मार्च 2026 में लेनदेन का कुल मूल्य 29.53 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के इसी महीने (24.77 लाख करोड़ रुपए) की तुलना में वार्षिक आधार पर 19% अधिक है। फरवरी की तुलना में भी इसमें 10% की वृद्धि दर्ज की गई है। लेनदेन की संख्या के मामले में भी नया रिकॉर्ड बना है। मार्च में कुल 22.64 अरब लेनदेन हुए, जो पिछले साल मार्च के 18.3 अरब के मुकाबले 24% की वृद्धि है।

तेल आयात पर निर्भरता घटाने के लिए तुरंत नीति बदलाव जरूरी

ए के भट्टाचार्य

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भारत की पेट्रोलिएम कंपनियों तथा सरकार की वित्तीय स्थिति पर तेल संकट का असर मापने के लिए ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत सही पैमाना नहीं है। इसके लिए कच्चे तेल की भारतीय बास्केट के दाम पर नजर रखना जरूरी है। भारतीय रिफाइनरों और सरकार के बाहरी खाते पर तेल संकट का असर इसी से आंका जा सकता है। 19 मार्च तक भारतीय बास्केट की कीमत लगभग 150 डॉलर प्रति बैरल थी। उसी दिन ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 105 से 108 डॉलर प्रति बैरल के बीच झूल रही थी।

भारतीय बास्केट की कीमत विभिन्न प्रकार के कच्चे तेल के मिश्रण से निकाली जाती है, जिसमें ओमान और दुबई तेल के सावर ग्रेड के साथ स्वीट ग्रेड ब्रेंट शामिल

होता है। भारतीय कंपनियों की रिफाइनिंग में सावर ग्रेड का अनुपात 79 होता है और ब्रेंट क्रूड का 21। इस अनुपात वाले मिश्रण की वजह से ही भारतीय बास्केट और ब्रेंट क्रूड के दामों में इतना अंतर दिखता है। इस अंतर की अनदेखी नहीं की जा सकती है क्योंकि इसी से पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस किस के संकट से जूझ रही है।

इसीलिए भारतीय रिफाइनरों के कामकाज पर कच्चे तेल के ऊंचे दामों का असर अभी पूरी तरह दिख ही नहीं पाया है। कुछ ही दिन में समाप्त होने जा रहे चालू वित्त वर्ष में भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की औसत कीमत लगभग 71 डॉलर प्रति बैरल रही। यह 2024-25 में भारतीय बास्केट की 78.56 डॉलर प्रति बैरल औसत कीमत से कुछ कम ही है। इसलिए कच्चे तेल के दाम के मामले में भारतीय तेल कंपनियों और



भारतीय अर्थव्यवस्था पश्चिम एशियाई युद्ध का असर मौजूदा वित्त वर्ष में पूरी तरह नहीं दिख सकेगा। लेकिन आने वाले वित्त वर्ष में इसका असर महसूस होगा क्योंकि संकट के शीघ्र समाधान के कोई संकेत नहीं हैं।

नरेंद्र मोदी सरकार अपने कार्यकाल (2014 से अब तक) में तेल कीमतों के मामले में अपेक्षाकृत भाग्यशाली रही है। मनमोहन सिंह सरकार के अंतिम तीन वर्षों में कच्चे तेल के भारतीय बास्केट की औसत सालाना कीमत 105 से 112 डॉलर प्रति बैरल के बीच रही। मगर मोदी सरकार के 12 वर्षों में औसत सालाना कीमत 46 से 93 डॉलर प्रति बैरल के बीच रही है। इनमें भी सात

वर्षों में तो तेल की औसत कीमत उनसे पिछले वर्षों की तुलना में कम ही रही। भारतीय रिफाइनर जो कच्चा तेल इस्तेमाल करते हैं, उनकी औसत सालाना कीमत पिछले दो वर्ष में 11 प्रतिशत और 5 प्रतिशत से अधिक गिर गई।

मगर कच्चे तेल के कम दाम वाले इन 12 वर्षों पर नजर डालें तो परेशान करने वाली एक बात दिखती है। क्या मोदी सरकार ने इस अवधि का इस्तेमाल पेट्रोलिएम के आयात पर देश की बढ़ती निर्भरता की समस्या दूर करने में किया? देश ने अपनी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के मामले में अच्छा काम किया है मगर क्या सरकार को आयात पर निर्भरता कम करने तथा देश के भीतर पेट्रोलिएम प्रोसेसिंग बढ़ाने पर भी इतना ही ध्यान देना चाहिए था?

सरकार ने बीते कुछ वर्षों में तेल आयात पर देश की निर्भरता कम करने के लिए कई

नीतिगत घोषणाएं और योजनाएं पेश की हैं। परंतु हकीकत कुछ और है। वर्ष 2014 से भारत के भीतर कच्चे तेल का उत्पादन हर वर्ष घटता जा रहा है। घरेलू उत्पादन 2014-15 में 3.59 करोड़ टन था, जो 2024-25 में घटकर 2.65 करोड़ टन रह गया। इस वित्त वर्ष में अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 तक देश में 2.38 करोड़ टन कच्चे तेल का उत्पादन हुआ, जिससे पता चलता है कि इस वर्ष भी उत्पादन में गिरावट ही होगी।

ध्यान देने की बात है कि इन वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी और कच्चे तेल की मांग भी बढ़ रही थी। कच्चे तेल का आयात 2014-15 के 18.9 करोड़ टन से बढ़कर 2024-25 में 24.3 करोड़ टन हो गया। इस तरह आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता 2014-15 में 84 प्रतिशत थी, जो बढ़कर पिछले वर्ष 90 प्रतिशत तक हो गई।

छत्तीसगढ़ को महिला फुटबॉल का स्वर्ण

रायपुर। छत्तीसगढ़ की महिला फुटबॉल टीम ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स-2026 के पहले संस्करण में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में झारखंड को 1-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। टीम की कप्तान किरण पिस्टा की व्यक्तिगत प्रतिभा इस जीत की सबसे बड़ी वजह रही।

मेज़बान राज्य ने जगदलपुर में ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिताओं के अंतिम चरण में पुरुषों की 4म400 मीटर रिले में रजत और पुरुषों की 1500 मीटर में कांस्य पदक भी अपने नाम किया। वहीं झारखंड के शिव कुमार सोरेन ने 100 मीटर के बाद 200 मीटर में भी स्वर्ण जीतकर शानदार डबल पूरा किया।

छत्तीसगढ़ की महिला टीम ने आक्रामक झारखंड के खिलाफ मिले एकमात्र मौके का पूरा फायदा उठाया, जब कप्तान किरण पिस्टा ने 61वें मिनट में विपक्षी डिफेंस की गलती का फायदा उठाते हुए गोल दागा। इसके बाद मेज़बान टीम ने बहुत को अंत तक बरकरार रखते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। किरण ने कहा,यह हमारे



लिए बहुत खास पल है क्योंकि पहली बार इतने सारे दर्शक हमें समर्थन देने आए। मुझे बहुत खुशी है कि हम अपने घरेलू दर्शकों के सामने स्वर्ण पदक जीत सके। पहली बार आयोजित हो रहे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 3800 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, तैराकी, भारोत्तोलन और कुश्ती जैसे सात खेल शामिल हैं, जबकि मल्लखंभ और कबड्डी प्रदर्शन खेल हैं।

जगदलपुर के क्रीड़ा परिसर में

मेज़बान छत्तीसगढ़ ने पुरुषों की 4म400 मीटर रिले में ओडिशा के बाद दूसरे स्थान पर रहकर रजत पदक जीता। ओडिशा ने 3८८.47 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण जीता, जबकि छत्तीसगढ़ ने 3८९.26 सेकंड में दौड़ पूरी की। झारखंड (3८९.62 सेकंड) को कांस्य मिला। इससे पहले मनीष कुमार ने पुरुषों की 1500 मीटर फाइनल में 4०1.50 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक जीतकर छत्तीसगढ़ की झोली भरी। इस स्पर्धा का स्वर्ण झारखंड के राहुल उरांव (4०1.18 सेकंड) ने जीता, जबकि महाराष्ट्र के कार्तिक करिहारपाल (4०1.23 सेकंड) को रजत पदक मिला।खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के पहले संस्करण के समापन में अब सिर्फ एक दिन शेष है और मेज़बान छत्तीसगढ़ तीन स्वर्ण, नौ रजत और छह कांस्य पदकों के साथ नौवें स्थान पर पहुंच गया है।कर्नाटक की रीथुश्री और नागिनी के दो स्वर्ण पदक जोड़ने के साथ तालिका में शीर्ष पर काबिज़ राज्य के खाते में अब 23 स्वर्ण, आठ रजत और सात कांस्य पदक हो गए हैं।

प्रदेश को मिली 15वें वित्त आयोग की 404 करोड़ की राशि



नगरीय निकायों में विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार

रायपुर। वित्तीय वर्ष के आखिरी 48 घंटों में छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन विभाग ने एक शानदार रिकॉर्ड कायम किया है. विभाग ने मिशन मोड में काम करते हुए राज्य के नगरीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग की 404.66 करोड़ रुपये की बड़ी राशि प्राप्त कर दिखाया.

दरअसल, लगातार प्रयासों से वित्तीय वर्ष खत्म होने के ठीक पहले 30 मार्च 2026 को भारत सरकार से 202.33 करोड़ रुपये

राज्य को प्राप्त हुई. उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाग द्वारा सभी निकायों को तुरंत राशि अंतरित की गई, और अगली किश्त की पात्रता के लिए तत्पश्चात तैयार कर त्वरित मांग प्रस्तुत किया गया. नियमानुसार ग्रांट ट्रांसफर सर्टिफिकेट समय सीमा में प्रस्तुत होने से केंद्र से अगले किस्त की राशि की पात्रता प्राप्त कर ली गई और कुछ ही घंटों में राशि भी प्राप्त हो गई.

महज 24 घंटे में हुआ पूरा प्रोसेस

मात्र एक दिन के भीतर

कोषालय टेजरी से राशि निकाली गई, निकायों को ट्रांसफर की गई और ग्रांट ट्रांसफर सर्टिफिकेट' जीटीसी तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दिया गया.

तुरंत मिली दूसरी किश्त

इस त्वरित कार्रवाई और केंद्र सरकार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के साथ बेहतरीन समन्वय का नतीजा यह रहा कि बिना समय गंवाए 202.33 करोड़ रुपये की दूसरी किश्त भी तुरंत मंजूर हो गई. इस प्रकार मान उप मुख्यमंत्री जी के लगातार मानिट्रिंग एवम केंद्र से बेहतर समन्वय से कुल 404.66 करोड़ रुपये की राशि छत्तीसगढ़ के शहरों के लिए प्राप्त कर ली गई. इस फंड के आने से अब प्रदेश के नगरीय निकायों में विकास कार्यों, पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं को एक नई रफ्तार मिलेगी।

नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ देवभोग मिल्क पाल्टर संघ का प्रदर्शन

रायपुर। नगर निगम रायपुर द्वारा शहर में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत छत्तीसगढ़ शासन के प्रतिष्ठित उपक्रम देवभोग के मिल्क पाल्टरों को हटाए जाने के विरोध में आज छत्तीसगढ़ प्रदेश देवभोग मिल्क पाल्टर संघ ने मोर्चा खोल दिया।आज नगर निगम के जोन क्रमांक 10 कार्यालय में बड़ी संख्या में पहुंचे संघ के सदस्यों ने निगम की कार्रवाई के प्रति अपना गहरा आक्रोश व्यक्त किया। विरोध स्वरूप संघ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कार्यालय परिसर में ही दूध के पैकेट फोड़कर अपना विरोध दर्ज करवाया। संघ का तर्क है कि शासन के उपक्रम को अतिक्रमण की श्रेणी में रखकर हटाना अनुचित है, जिससे न केवल स्वरोजगार प्रभावित हो रहा है, बल्कि आम जनता के लिए दुग्ध आपूर्ति में भी बाधा आ रही है।जोन क्रमांक 10 के कर्मचारी योगेश यदु

डीएड अभ्यर्थियों के संघर्ष का 98वां दिन

घुटनों के बल मार्च कर उठाई न्याय की आवाज, 10 भेजे गए जेल

रायपुर। छत्तीसगढ़ के 2300 चर्चवर्ति डीएड अभ्यर्थियों का संघर्ष आज अपने 98वें दिन में प्रवेश कर चुका है। यह केवल एक आंदोलन नहीं, बल्कि न्याय, अधिकार और सम्मान की लड़ाई बन गया है, जहां अभ्यर्थी अपनी पीड़ा और उम्मीदों के साथ हर दिन सरकार से गुहार लगा रहे हैं। आज का आंदोलन भावुक और पीड़ादायक रूप ले लिया, जब अभ्यर्थियों ने अपने हक की मांग को लेकर घुटनों के बल चलकर 2300 पदों पर शीश न्युक्ति की अपील की। इस दौरान कई अभ्यर्थियों के घुटने लहलुहान हो गए और कई के पैरों में गंभीर घाव व फफोले पड़ गए, फिर भी उनका हौसला नहीं टूटा। इसी क्रम में आंदोलन को



और अधिक गंभीरता से प्रस्तुत करने के लिए अभ्यर्थियों ने तृता धरना स्थल के पीछे स्थित तालाब में जल समाधि लेने का प्रयास किया। यह दुःख अत्यंत मार्मिक और झुकझोर देने वाला था, जहां अपने अधिकारों से वंचित युवा अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में उतर गए। इस दौरान कई अभ्यर्थी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

बल्कि उस व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न है, जो अपने ही युवाओं को इस स्थिति में पहुंचा रही है। वहीं 10 डीएड अभ्यर्थी को मेंडिकल चेकअप के बहाने झूठ बोल कर अहमपुर थाना ले जाया गया और भारतीय न्याय संहिता की धारा 170, 126 और 136 के तहत कार्रवाई करते हुए सेंट्रल जेल भेज दिया गया।

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

मोदी राज में महंगाई बढ़ी गरीब और गरीब हुये: बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, महंगाई से देश के नागरिकों की कमर टूटती जा रही है। 2014 में जो गैस का सिलेंडर 410 रु. का था, आज वह 980 रु. के पार है। पेट्रोल के दाम 70 रु. प्रति लीटर से बढ़कर 102 रु. प्रति लीटर के पार हो गए हैं जबकि डीजल के दाम 55 रु. प्रति लीटर से बढ़कर 100 रु. प्रति लीटर के करीब पहुंच गए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मोदी सरकार देश को असमानता और कर्ज की आग में झोंका, दिया सिर्फ धना सेठों को मौका। हाल ही में आई 'ऑक्सफेम' की रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के 5 प्रतिशत अमीर लोगों के पास देश की 60 प्रतिशत से ज्यादा संपत्ति है और नीचे के 50 प्रतिशत लोगों के पास देश की मात्र 3 प्रतिशत संपत्ति। 'ऑक्सफेम' की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी की विभीषिका में भी देश के 100 बड़े पूंजीपतियों ने 13 लाख करोड़ रुपए कमाए पर 12 करोड़ मेहनतकार लोगों ने अपना रोजगार खो दिया। मोदी जी के कई मित्रों की आय तो 1,000 रु. करोड़ प्रतिदिन बढ़ रही है। महामारी की विभीषिका में 84 करोड़ लोगों की आवेदनी घंट घई लेकिन सरकार की मेहरबानी धनासेठों पर रही।

भाजपा नहीं चाहती झीरम का सच सामने आये : शुक्ला

रायपुर। भाजपा झीरम का सच सामने नहीं आने देना चाहती। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि झीरम घाटी कांक एक ऐसा कांड था जिसने कांग्रेस के नेतृत्व की एक पूरी पीढ़ी को ही समाप्त कर दिया था। स्वतंत्र भारत में हुई दुर्दांत और हृदय विदारक घटना भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में डॉ. रमन सिंह के राज में घटित हुई थी इसके गुनाहगारों को सजा जरूर मिलनी चाहिये। भाजपा का पूरा नेतृत्व झीरम के सच को दबाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य की एसआईटी ने झीरम के जांच क्यों शुरू नहीं किया? प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा डरती है झीरम का सच सामने आ जायेगा तो वह बेनकाब हो जायेगी। रमन सिंह से बड़ा कर्तु शायद आजाद भारत में आज तक नहीं हुआ। एक साथ विपक्ष के 32 नेताओं की हत्या हो गयी और तत्कालीन सरकार सच सामने आने देने से रोकने में पूरी ताकत लगा रखी थी। भाजपा के बड़े नेता जीरम की जांच को रोकने लगातार कोशिशें करते रहे उसमें साफ है झीरम के पीछे तत्कालीन भाजपा सरकार की भूमिका संदिग्ध थी। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस सरकार ने झीरम हमले की जांच के लिये एसआईटी का गठन किया था।

भाजपा नेता के अवैध शराब के धंधा को किसका संरक्षण था?

रायपुर। कांग्रेस जिला भाजपा अनुसूचित जाति अध्यक्ष के ढाबा में अवैध शराब पकड़ने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कांग्रेस जिला भाजपा एससी, एसटी अध्यक्ष ईश्वर कावड़े के ढाबा में अवैध शराब बेचा जा रहा था। आखिर इन्हें किसका संरक्षण है ? ईश्वर कावड़े की तस्वीर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह, गुहमंजरी विजय शर्मा के साथ वायरल हो रही है। लगातार भाजपा नेताओं के अवैध कारोबार का पकड़े जा रहे है। जिस प्रकार से अवैध शराब, अफीम की खेती,रेत तस्करी, में भाजपा नेताओं की संलिप्तता उजागर हो रही है अब भाजपा को अपने संगठन एक तस्कर प्रकोष्ठ बना लेना चाहिये। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा राजनांदगांव में महतारी एक्सप्रेस का उपयोग शराब तस्करी के लिए किया जा रहा था। मुंगेली में स्कूल को अवैध शराब का डंप यार्ड बना दिया गया। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा, राजनांदगांव सहित प्रदेश के सभी शहरों में नकली होलोग्राम लगा कर अवैध शराब बेची जा रही। पड़ोसी राज्यों उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड से बड़ी मात्रा में शराब लाकर प्रदेश में बेची जा रही। शराब के इस अवैध कारोबार में सरकार खुद शामिल है।

मामूली बढ़ोतरी से मजदूरों के साथ न्याय नहीं : सिंह

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह ने राज्य में न्यूनतम वेतन में की गई हालिया वृद्धि को लेकर कहा कि यह बढ़ोतरी महज औपचारिकता है और महंगाई के इस दौर में श्रमिकों के साथ अन्याय है। आज के समय में बढ़ती महंगाई, खाद्य पदार्थों, पेट्रोल -डीजल की कीमतों, किराया और दैनिक जरूरतों के खर्च को देखते हुए यह राशि बेहद अपर्याप्त है। दिखावे कि मामूली बढ़ोतरी से श्रमिकों के जीवन स्तर में कोई वास्तविक सुधार नहीं होने वाला। प्रदेश प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित नेशनल फ्लोर वेज National Floor Wage हम और मजदूरों के हितों को अनदेखी कर, केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित अकुशल श्रमिकों के लिए 20,358 प्रति माह तय होने के बावजूद विष्णुदेव साय सरकार 11,402 प्रतिमाह तय कि है और अत्यंत कुशल श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित 26,910 प्रतिमाह की जगह 13,612 प्रतिमाह इस सरकार ने तय किया है। यह दर्शाता है कि राज्य सरकार श्रमिकों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार भले ही अपनी मामूली बहुत दिखा कर अपनी उपलब्धियां दिखाने की कोशिश कर रही है।

महतारी वंदन के नाम पर महिलाओं से धोखा: वंदना

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने भाजपा सरकार के नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना नारी सशक्तिकरण के लिए लागू हुई यह योजना में पिछले 2 साल में ई केवाईसी के नाम पर 5 लाख से अधिक महिलाओं का नाम सूची से काटने का काम किया गया है। लेकिन छूटे हुए पात्र महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ दिलाने के लिए फॉर्म नहीं भरया जा रहा है और अभी तक इसके लिए सरकार की कोई नीति दिखाई नहीं दे रहा है। भाजपा सरकार महिलाओं को धोखा दे रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि चुनाव के समय भाजपा का वादा था कि सभी प्रत्येक विवाहित महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन जैसे ही सरकार बनती है वैसे ही विभिन्न तरह के नियम कानून ले आते हैं। प्रदेश में लगभग डेढ़ करोड़ महिलाएं विवाहित हैंगी, उसमें से करीबन 1 करोड़ महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिलना था। महतारी वंदन योजना के प्रथम चरण में सरकार दावा करती थी कि 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है लेकिन लगातार ई केवाईसी के नाम पर महिलाओं का नाम काटने का प्रक्रिया चल रहा है।

लोक निर्माण विभाग के लिए ऐतिहासिक रहा बीता वित्तीय वर्ष,

राज्य निर्माण के बाद मिली सबसे ज्यादा कार्यों को मंजूरी

रायपुर। लोक निर्माण विभाग के लिए विगत 31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष 2025-26 ऐतिहासिक रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में विभाग ने राज्य के निर्माण के बाद से अब तक सबसे ज्यादा कार्यों और राशि के प्रशासकीय स्वीकृति के आदेश जारी किए हैं।

वित्तीय वर्ष में विभाग द्वारा कुल 993 कार्यों के लिए 9129 करोड़ 18 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। यह राशि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के बाद से किसी एक वर्ष में स्वीकृत सर्वाधिक राशि के दोगुने से भी ज्यादा है। वर्ष 2025-26 में मंजूरी की गई राशि 2024-25 में स्वीकृत 2589 करोड़ 89 लाख रुपए की तुलना में तिगुने से

भी ज्यादा है, जबकि कार्यों की संख्या दोगुने से भी अधिक है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में लोक निर्माण विभाग ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की मांगों, जरूरतों और जन आकांक्षाओं को देखते हुए उप मुख्यमंत्री तथा विभागीय मंत्री अरुण साव के निर्देश पर 1925 नए कार्यों को शामिल करते हुए इनके लिए 2287 करोड़ रुपए के प्रावधान किए थे। पिछले वर्ष के बजट में राज्य निर्माण के बाद से सर्वाधिक संख्या में नए कार्यों के प्रस्ताव शामिल किए गए थे। बजट में शामिल नए कार्यों को प्राथमिकता में रखते हुए बड़ी संख्या में इनकी मंजूरी के



आदेश जारी किए गए हैं उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने प्रदेशभर में सड़कों और पुलों के कार्यों को गति देने प्रस्तावित कार्यों के जल्द से जल्द डीपीआर तैयार कर ज्यादा से ज्यादा कार्यों की स्वीकृति के निर्देश दिए थे। उनके निर्देश पर विभाग ने सक्रियता और तत्परता से अमल करते हुए बीते वित्तीय वर्ष में अब तक के सर्वाधिक 993 कार्यों के लिए

9129 करोड़ की राशि को मंजूरी दी है। उप मुख्यमंत्री साव ने इस तत्परता के लिए सभी विभागीय अधिकारियों और अमले की पीठ थपथपाते हुए कहा कि सरकार राज्य की अधोसंरचना को मजबूत करने अभूतपूर्व गति से कार्य कर रही है। रिकॉर्ड संख्या में सड़कों और पुलों को स्वीकृति देकर शहरों, गांवों और वनांचलों को जोड़ने का अभियान चल किया गया है। हमारी प्राथमिकता हर पहुंचविहीन क्षेत्र तक बेहतर सड़क सुविधा पहुंचाना है, जिससे विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। सरकार सड़क नेटवर्क का सहज जाल बिछाने पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। लोक

निर्माण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में 141 सड़कों और पुलों के लिए 2013 करोड़, 2017-18 में 300 कार्यों के लिए 2311 करोड़, 2018-19 में 154 कार्यों के लिए 4544 करोड़ , 2019-20 में 312 कार्यों के लिए 2402 करोड़ और 2020-21 में 345 कार्यों के लिए 3797 करोड़ की स्वीकृति दी गई थी। विभाग ने वर्ष 2021-22 में 531 कार्यों के लिए 4482 करोड़ , 2022-23 में 466 कार्यों के लिए 2656 करोड़ रुपए, 2023-24 में 355 कार्यों के लिए 3753 करोड़ तथा 2024-25 में 436 कार्यों के लिए 2590 करोड़ रुपए के कार्यों को प्रशासकीय मंजूरी प्रदान की थी।

बिजली दर वृद्धि खिलाफ आम आदमी पार्टी ने

बिजली ऑफिस का घेराव कर ज्ञापन दिया

रायपुर। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित बिजली दर वृद्धि और बदहाल बिजली व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला हुए आज 2 अप्रैल को बिरगांव के बिजली ऑफिस का घेराव कर अपनी 6 सूत्री मांगो पर वितरण कंपनी के एमडी के नाम ज्ञापन दिया । पार्टी ने कहा कि सरकार को जनता पर बार-बार बिजली दर बढ़ाकर आर्थिक बोझ डालने के बजाय बिजली उत्पादन और प्रबंधन सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती, स्मार्ट मीटर तकनीक का दुरुपयोग, और लगातार खराब प्रबंधन से आम जनता त्रस्त है। यह स्थिति दर्शाती है कि ऊर्जा विभाग



पूरी तरह ब्यूरोक्रेट्स के प्रभाव में काम कर रहा है, जिससे जनहित की अनदेखी हो रही है। नए टेंडर सिस्टम पर गंभीर सवाल आने से हाल ही में लागू किए गए नए टेंडर सिस्टम को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी ने कहा कि यह पूरा सिस्टम अधिकारियों की कार्यशैली का गंभीर सवाल खड़े करता है और यही कारण है कि अघोषित बिजली कटौती की समस्या, विभाग के एमडी की लापरवाही और लगातार खराब प्रबंधन के कारण प्रदेश की बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। आप की प्रमुख मांगें- प्रस्तावित बिजली दर वृद्धि को तत्काल वापस लिया जाए बिजली विभाग के वर्तमान एमडी को तुरंत बदला जाए बड़े अधिकारियों के कार्यों की कड़ी समीक्षा की जाए टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए।